https://www.facebook.com/KamalSandeshBjp/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

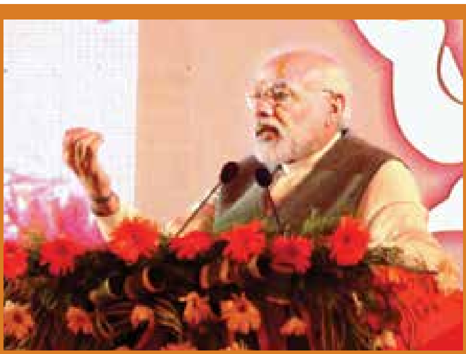

विकास के साथ-साथ सुशासन बहुत जरूरी है : नरेन्द्र मोदी

वर्ष-12, अंक-09, 01-15 मई, 2017 (पाक्षिक) ₹20

'तीव्र आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर भारत'

भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग आना अभी बाकी है: अमित शाह

गरीब जनता के मानस में मोदीजी के प्रति श्रद्धा, आदर और विश्वास का भाव मजबूत हुआ है

एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और अभूतपूर्व निर्णय

भुवनेश्वर (ओडिशा) में आयोजित भाजपा पदाधिकारियों की बैठक के दृश्य

भाजपा पदाधिकारियों की बैठक का दीप–प्रज्ज्वलन कर उद्घाटन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण

भाजपा पदाधिकारियों की बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) श्री रामलाल

भुवनेश्वर (ओडिशा) में संपन्न भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के चित्र

जन–अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

श्री मोदी को प्रतीक–चिन्ह भेंटकर स्वागत करते ओडिशा प्रदेश भाजपा नेतागण

प्रधानमंत्री एवं भाजपाध्यक्ष का अभिनंदन करते वरिष्ठ भाजपा नेतागण

कार्यकारिणी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी एवं केंद्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली

कमल संदेश
पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइटः www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग आना अभी बाकी हैः अमित शाह**

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 15 एवं 16 अप्रैल 2017 को भुवनेश्वर (ओडिशा) में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने प्रेरक अध्यक्षीय उद्‌बोधन देते हुए जहां हाल ही...

वैचारिकी

कांग्रेस बनाम जनसंघ 23

श्रद्धांजलि

गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 25

अन्य

विकास के साथ-साथ सुशासन बहुत जरूरी है : नरेन्द्र मोदी 16

सेवा यात्रा के इस यज्ञ ने पूरे मध्य प्रदेश को एकजुट करने... 18

भाजपा ने दिल्ली, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और... 19

केंद्र सरकार ने सभी श्रेणियों के वाहनों से सभी तरह की बत्तियां... 21

भारत-बांग्लादेश के बीच 22 समझौतों पर हस्ताक्षर 26

वरिष्ठ नागरिकों के लिए "राष्ट्रीय वयोश्री योजना" का शुभारम्भ 27

संसद के दोनों सदनों ने 18 विधेयक को दी मंजूरी 30

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): आवास से घर तक 31

यह विजय यात्रा मोदीजी द्वारा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन... 32

संगठनात्मक गतिविधियां

10 **गरीब जनता के मानस में मोदीजी के प्रति श्रद्धा, आदर और विश्वास का भाव मजबूत हुआ है**

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी...

14 **एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और अभूतपूर्व निर्णय**

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद...

सरकार की उपलब्धियां

20 **प्रधानमंत्री द्वारा 'आधार' आधारित नया 'भीम' ऐप लॉन्च**

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को आधार नंबर से चलने वाला नया "भीम"...

21 **भारत सरकार की कुछ प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाएं**

केन्द्रीय सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 15 अप्रैल को भारत...

प्रकाशक एवं मुद्रकः डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

वास्तव में, भारत में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं, जो लोग गरीबों और मध्य वर्ग को लूटे हैं, उन्हें लूटा हुआ धन वापस करना ही होगा।

@AmitShah

आज, हमारी जिम्मेदारी केवल पार्टी संगठन को मजबूत करने तक की नहीं रह गई है, बल्कि देश की राजनीतिक व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाना भी है।

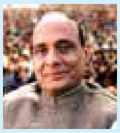

@rajnathsingh

कश्मीरी युवा भी भारत की प्रगति में योगदान कर रहे हैं। ऐसे राज्यों को उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो इन्हें निशाना बना रहे हैं।

facebook

'नमस्ते सर्वदे' मंत्रोच्चारण के साथ ही हम नर्मदा से बोटाद तक जल लाने का स्वागत करते हैं। सौनी योजना सौराष्ट्र के लिए परिवर्तनकारी है और इससे किसानों को लाभ मिल रहा है।

-नरेन्द्र मोदी

भारत वैश्विक एफडीआई कांफिडेंस सूचकांक में 8वें स्थान पर पहुंच गया है।

-एम. वेंकैया नायडू

स्वस्थ भारत/किलकारी योजना के अन्तर्गत 5.5 करोड़ से भी अधिक की सफल कॉलें लाभार्थियों को की गई हैं।

-जे.पी. नड्डा

व्यंग्य चित्र

साभार: नई दुनिया

पाथेय

कोई भी पार्टी भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण और जटिल समस्याओं से घिरे हुऐ देश का शासन डंडे के बल पर नहीं चला सकती। यहां तक कि देश की एकता और अखंडता को भी डंडे का प्रयोग करके कायम नहीं रखा जा सकता अथवा मजबूत नहीं किया जा सकता। केवल कानून और संविधान ही एकता की भावना पैदा नहीं कर सकते। यह केवल तभी पैदा की जा सकती है, जब प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क और हृदय में यह भावना अनुभव करे कि यह राष्ट्र उसका अपना है और यह अपनत्व की भावना तभी पैदा होती है, जब प्रत्येक नागरिक चाहे उसकी जाति, धर्म, या श्रेणी कुछ भी हो, यह अनुभव करे कि उसकी देखभाल की जा रही है।

-कुशाभाऊ ठाकरे

अब हर भारतीय 'वीआईपी'

'लालबत्ती' पर रोक लगने से देश में वर्षों से पनपती 'वीआईपी कल्चर' को बड़ा झटका लगा है। 'स्टेटस सिंबल' बन चुकी 'लालबत्ती' लगातार दुरुपयोग के कारण सुर्खियों में छाई रहती थी। वास्तव में यदि देखा जाए तो 'लालबत्ती' के पीछे वही औपनिवेशिक मानसिकता थी, जो ब्रिटिश राज के लिए एक विशेषाधिकार प्राप्त समर्थक वर्ग को खड़ा करने के पीछे थी। यह बड़ी विडंबना है कि लोकतंत्र में भी वही मानसिकता किसी न किसी रूप में अब तक छाई रही। दरअसल, जहां वंशवाद, भाई-भतीजावाद एवं जातिवाद लोकतंत्र के लिए जहर बन गया है, वहीं 'वीआईपी कल्चर' लोकतंत्र की आत्मा पर कुठाराघात है। 'लालबत्ती' पर रोक लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ठीक ही कहा कि 'हर भारतीय विशिष्ट है, हर भारतीय वीआईपी है।'

लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब स्वयं को देश का 'प्रधान सेवक' घोषित किया, तब ही यह स्पष्ट हो गया था कि वह लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप कार्य-संस्कृति में परिवर्तन चाहते हैं। संदेश साफ था - लोकतंत्र में कोई 'शासक वर्ग' नहीं हो सकता, सब जनता के 'सेवक' हैं। शासक वर्ग का होने का अहंकार कहीं न कहीं औपनिवेशिक विरासत की देन है, जो स्वतंत्रता के बाद भी राजनेताओं एवं अफसरशाहों को अपने चपेट में लेती रही है। क्या लोकतंत्र में 'शासक' एवं 'शासित' जैसे वर्गीकरण का स्थान है? 'शासक' होने का भाव न केवल लोकतांत्रिक भावना के विपरीत है, बल्कि इससे वंशवाद, भाई-भतीजावाद एवं जातिवाद जैसे कुवृत्तियों का जन्म होता है, जो दिन-प्रतिदिन लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर देती है। किसी परिवार, जाति या गुट का 'राज' कायम करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त किसी वर्ग का गढ़ा जाना कुछ और नहीं बल्कि लोकतंत्र का विकृतिकरण है। भारतीय राजनीति में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जब किसी परिवार ने पार्टी पर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए अपने विशेषाधिकार प्राप्त समर्थकों को भ्रष्टाचार एवं लूट करने की खुली छूट दे दी। यदि गहराई से देखा जाए तो इसमें किसी को शायद ही संशय हो कि 'वीआईपी कल्चर' कहीं न कहीं व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। यदि राजनीति को सत्ता हथियाने तथा लोगों पर राज करने के उपकरण रूप में देखा जाने लगे, तब देश कभी उन्नत एवं समृद्ध नहीं हो सकता।

> लोकतंत्र में कोई शासक वर्ग नहीं हो सकता, सब जनता के सेवक हैं। शासक वर्ग का होने का अहंकार कहीं न कहीं औपनिवेशिक विरासत की देन है, जो स्वतंत्रता के बाद भी राजनेताओं एवं अफसरशाहों को अपने चपेट में लेती रही है। क्या लोकतंत्र में 'शासक' एवं 'शासित' जैसे वर्गीकरण का स्थान है? 'शासक' होने का भाव न केवल लोकतांत्रिक भावना के विपरीत है, बल्कि इससे वंशवाद, भाई-भतीजावाद एवं जातिवाद जैसे कुवृत्तियों का जन्म होता है, जो दिन-प्रतिदिन लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर देती है।

भारतीय जनता पार्टी का जन्म 'राजनीति' को एक नया अर्थ देने के लिए हुआ है। स्वतंत्रता पश्चात् जैसे-जैसे कांग्रेस वंशवाद की पर्याय बनती गई, इसके नेता राजनीति को सत्ता हथियाने एवं जनता पर राज करने के माध्यम के रूप में देखने लगे। कांग्रेस में व्याप्त ऐसी ही मानसिकता के कारण इसकी आज यह दुर्गति हुई है और लोग अब इसे कुशासन, भ्रष्टाचार एवं वंशवाद के लिए याद करते हैं। जनता को अब भाजपा के रूप में एक ऐसा विकल्प मिल चुका है, जिसके कंधों पर देश की लोकतांत्रिक भावना तथा जनाकांक्षाओं को पूरा करने का दायित्व है। एक ओर जब देश तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहा है, तो सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करना भाजपा की प्राथमिकता है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बार-बार कहा है की देश की अपेक्षा हमसे केवल सुशासन की नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की है। प्रधानमंत्री ने स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर सरकारी अधिकारियों एवं राजनैतिक नेताओं में दायित्व बोध जगाया तथा देश में एक नई कार्य संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया है। राजनीति सत्ता और पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा तथा देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए होनी चाहिए। यह बात समझनी पड़ेगी कि राजनीति स्वार्थी, भ्रष्ट तथा सत्तालोलुप लोगों की शरणस्थली नहीं, बल्कि मां भारती को उच्च सिंहासन पर आरूढ़ करने का स्वप्न देखने वाले निःस्वार्थ कर्मयोगियों की साधना है। 'लालबत्ती' बंद करने का निर्णय 'वीआईपी कल्चर' पर एक कड़ा प्रहार तो है ही, साथ ही यह सुशासन को सही अर्थों में परिभाषित करता है जिसका अर्थ अब 'राज' करना नहीं, बल्कि 'सेवा' करना है। व्यवस्था में जब तक 'सेवा' की भावना एक मिशन नहीं बन जाती, तब तक मां भारती परम् वैभव को प्राप्त नहीं कर पायेगी। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग आना अभी बाकी है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 15 एवं 16 अप्रैल 2017 को भुवनेश्वर (ओडिशा) में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने प्रेरक अध्यक्षीय उद्‌बोधन देते हुए जहां हाल ही में संपन्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी को मिली जीत पर प्रतिनिधियों को बधाई दी, वहीं संगठन को और सशक्त करने एवं आगामी चुनावों में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने का आह्वान किया। श्री शाह ने कहा कि लोग कहते हैं कि यह भाजपा का स्वर्णिम समय है पर मैं कहता हूं कि स्वर्णिम समय तब आएगा जब केरल, बंगाल और ओडिशा आदि राज्यों में भाजपा की सरकार होगी। अब जब हमें लगातार विजय मिल रही है तब हमारे अंदर आलस्य का निर्माण न होने पाए, बल्कि विस्तार की प्यास हमें परिश्रम की पराकाष्ठा की प्रेरणा दे।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने भुवनेश्वर के जनता मैदान में श्री भीम भोई परिसर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित किया। अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में उन्होंने पांच राज्य के विधानसभा चुनावों में भाजपा की अप्रत्याशित विजय, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के कामकाज और संगठन विस्तार के कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की।

श्री शाह ने कहा कि आज हम महाप्रभु जगन्नाथ की पावन भूमि पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में संपन्न हुए पिछले राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से अब तक के तीन महीने में देश में बहुत बड़े स्तर पर राजनीतिक बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि इस दौरान संपन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में से चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई है। यहां हमें तीन चौथाई से ज्यादा बहुमत प्राप्त हुआ है, साथ ही गोवा और मणिपुर में भी पार्टी को सबसे अधिक वोट मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा की इस अभूतपूर्व विजय का मुख्य कारण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी सरकार

की गरीब कल्याण की नीति को नीचे तक पहुंचाने की कार्य-योजना और पार्टी के कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम है। उन्होंने कहा कि अब राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानने पर विवश हो गए हैं कि श्री नरेन्द्र मोदी जी आजादी के बाद देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पांच राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व विजय पर कार्यकारिणी के सदस्यों से अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का करतल ध्वनि से स्वागत करने की अपील की। (सभी सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत किया।) उन्होंने पांचों राज्यों की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके विश्वास व आकांक्षाओं पर शत-प्रतिशत खरे उतरने का काम राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करेंगी और राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कार्यकारिणी से लेकर अब तक के तीन महीने में महत्त्वपूर्ण जीएसटी विधायक को दोनों सदनों में पारित किया गया जो एक राष्ट्र, एक टैक्स की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस दौरान पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार समाज के ऐसे गुमनाम मनीषियों, समाजसेवियों और बुद्धिजीवियों को यह पुरस्कार दिए गए हैं जिन्होंने देश व समाज के लिए कई अकल्पनीय कार्य किये हैं। सही मायनों में पद्म पुरस्कारों का जनतांत्रिककरण किया गया है जो कि एक अनूठी पहल है। अब पद्म पुरस्कारों के लिए कोई भी व्यक्ति स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच होती है और फिर पुरस्कारों के लिए उपयुक्त लोगों का नाम फाइनल किया जाता है। यदि इस बार की पद्म पुरस्कारों की सूची का एनालिसिस किया जाय तो पता चलेगा कि देश में कितना बड़ा बदलाव आया है।

श्री शाह ने कहा कि 2014 में 30 वर्ष के पश्चात पहली बार किसी एक दल को बहुमत मिला और आजादी के बाद तो पहली बार किसी गैर-कांग्रेसी दल को अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिला और केंद्र में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि इसके बाद हुए हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत हासिल हुई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनीं। बिहार और दिल्ली में भी हमारे वोट प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई। 2014 के बाद जितने भी चुनाव, उप-चुनाव अथवा स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, उसमें हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की जो भाजपा के दिनोंदिन बढ़ते हुए जनाधार और भाजपा में देश की जनता की गहरी आस्था का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम पर बोलते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में पहली बार सपा-बसपा के क्रम टूटने के साथ ही जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हुआ है और 'पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस' के एक नए युग की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा जनादेश आजादी के बाद किसी भी पार्टी को नसीब नहीं हुआ जितना बड़ा जनादेश इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को तीन-चौथाई बहुमत से जीत नसीब हुई है। उत्तराखंड के लिए जो हमने कहा था कि इस प्रदेश को श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया और मोदी जी इसे संवारेंगे – इसे राज्य की जनता ने हृदय से स्वीकार किया है।

विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत से विपक्ष बौखलाया हुआ है। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वे रह-रह कर इवीएम को लेकर आरोप लगाते रहते हैं। उन्होंने विपक्ष को कठघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि क्या यूपीए-1 और यूपीए-2 की जीत क्या इवीएम से नहीं हुआ था, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बैलेट पेपर से चुनकर आई थी और क्या अभी पंजाब में कांग्रेस की जीत ईवीएम के कारण हुई है?

महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनीं। बिहार और दिल्ली में भी हमारे वोट प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद जितने भी चुनाव, उप-चुनाव अथवा स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, उसमें हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की जो भाजपा के दिनोंदिन बढ़ते हुए जनाधार और भाजपा में देश की जनता की गहरी आस्था का द्योतक है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कई राजनीतिक पंडित 2014 को भाजपा का स्वर्णिम युग बताते थे, आज वे 2017 को भी भाजपा का स्वर्णिम युग बता रहे हैं लेकिन पार्टी का स्वर्णिम युग आना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि यह स्वर्णिम युग तभी आयेगा जब केरल, बंगाल, तमिलनाडु के साथ-साथ उत्तर-पूर्व के राज्यों में भी भाजपा की सरकार बनेगी और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एवं कच्छ से लेकर कामरूप तक संगठन का विस्तार होगा। विजय की यह भूख और बढ़नी चाहिए, हम अथक पुरुषार्थ से प्रेरणा लेकर और अधिक तत्परता के साथ काम करने के लिए कृतसंकल्पित हों।

श्री शाह ने कहा कि आगामी मई में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के तीन साल पूरे हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि इन तीन वर्षों में मोदी सरकार ने इतने सारे काम किये हैं कि इनमें से एक भी काम अपने पूरे कार्यकाल तक में कई सरकारें पूरा नहीं कर पातीं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार की तीन साल की कुछ प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा करना यहां आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के संग्रह में वृद्धि हुई है, डिमोनेटाईजेशन के द्वारा काले-धन के संग्रह पर अंकुश लगाया गया है, काले-धन को अर्थव्यवस्था से ख़त्म करने के लिए एक-के-बाद-एक कई कदम उठाये गए हैं, टैक्सेशन को पारदर्शी बनाया गया और राजनीतिक चंदों को 2000 कैश तक सीमित करके चंदे की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने की पहल की गई है। चाहे बेनामी संपत्ति पर क़ानून की बात हो, शत्रु संपत्ति पर कार्रवाई की बात हो या फिर शेल कंपनियों के खिलाफ मुहिम की बात - एनडीए सरकार ने हर मोर्चे पर सुधार कार्यक्रम की नींव रखी है।

श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग का गठन करके और राज्यों को मिलने वाले शेयर को बढ़ा कर फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का काम किया गया है, बजट की प्रक्रिया को 31 मार्च से पहले ही पूरा कर के एक अप्रैल से बजट के प्रावधानों को लागू करने की शुरुआत करके एनडीए सरकार ने एक नया मानदंड स्थापित किया है। साथ ही, रेल बजट को आम बजट में समायोजित करके विकास की गति को तेज करने के प्रयास किये गए हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ठोस पहल करते हुए डेढ़ साल में ही लगभग 2 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गए हैं, जन-धन योजना के अंतर्गत लगभग 29 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोल कर उन्हें देश के अर्थतंत्र की मुख्यधारा से जोड़ा गया है, मुद्रा बैंक के माध्यम से देश के लगभग 7.32 करोड़ लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराये गए हैं, भीम ऐप की शुरुआत कर देश भर में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है और आजादी के 70 साल बाद भी बिजली से वंचित 18000 गांवों में से 13000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा किया गया है।

श्री शाह ने कहा कि किसानों की भलाई के लिए केंद्र की एनडीए सरकार ने कई काम किये हैं चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, स्वायल हेल्थ कार्ड की योजना हो, यूरिया उत्पादन में वृद्धि और खाद के दाम कम करने की बात हो।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 40 वर्षों से लंबित 'OROP' को एक साल में लागू कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा-नीत एनडीए सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान और अपनी संवेदना को प्रकट करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की विदेश नीति ने एक नया आयाम स्थापित किया गया है। साथ ही,

पेरिस समझौते में पर्यावरण को बचाने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दुनिया भर में सराहा गया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इन तीन सालों में हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। यहां तक कि हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सके हैं। अंतरिक्ष में एक साथ 104 उपग्रह को स्थापित करके हमने अंतरिक्ष विकास में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर विकास में पीछे छूट गए समाज के वंचितों के प्रति विकास की प्रतिबद्धता हमने दर्शाई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ और नमामि गंगे के माध्यम से हमने जन-समस्याओं को जन-आंदोलन बनाने का काम किया है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने न्यू इंडिया की परिकल्पना को देश के सामने रखा है जो हमारे नौजवानों की मेधा शक्ति को एक नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि 2022 में जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तब देश कैसा हो, इसके विकास का मॉडल कैसा होना चाहिए, यह प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिचायक है। 2022 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जुट गई है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को पॉलिसी पैरालिसिस से मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि लोगों को अच्छे लगने वाले फैसले नहीं, बल्कि लोगों के लिए अच्छे फैसले लिए जाने की जरूरत है और मोदी सरकार ऐसे ही निर्णायक फैसले ले रही है जो देश और जनता के लिए अच्छे हों, यह हमारी सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचायक है। साथ ही, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2019 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राजग की सरकार बनेगी और हम जनता की भलाई के लिए अहर्निश काम करेंगे।

श्री शाह ने कहा कि भाजपा केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में संगठन के कार्यकर्ताओं पर हिंसात्मक हमले की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि यदि विचारों को दबाने के लिए इस तरह से पार्टियां भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हिंसात्मक हमले करती है तो ऐसे में लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जा सकती है? उन्होंने कहा कि यदि इन राज्यों में सत्ताधारी पार्टियां यह सोचती हैं कि वे हिंसा के जरिये भारतीय जनता पार्टी के विचारों को विस्तारित करने से रोकने में सफल हो जायेंगे तो यह उनकी भूल है। वे ऐसा करने में कभी सफल नहीं हो पायेंगे, भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूती के साथ इन राज्यों में उभर कर आयेगी।

आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अभी दिल्ली में शुंगलू कमिटी की रिपोर्ट में जो सच्चाई सामने आई है, उससे यह स्पष्ट है कि राजनीतिक शुचिता का इससे बड़ा उल्लंघन और नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को विशाल जीत हासिल हुई है और पार्टी दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में भी अच्छी सफलता हासिल करेगी।

श्री शाह ने कहा कि यह वर्ष पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ष को बड़े पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी अधिकृत रूप से इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया है, हमारी राज्य सरकारों को भी इसके लिए कार्ययोजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष में संगठन के विस्तार व विकास के लिए लाखों कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है जो काफी उत्साहवर्द्धक है। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं इसमें अपनी भागीदारी दूंगा एवं विभिन्न राज्यों में बूथ स्तर पर प्रवास करूंगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल, गुजरात और कर्नाटक में भी अबकी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन होगा।

ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में 20 सालों से बीजद की सरकार है। उन्होंने कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य लगातार विकास की नई कहानियां लिख रहे हैं, वहीं ओडिशा विकास के हर मापदंडों में काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि यहां न तो लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है, न लोगों को बिजली मिल रही है और न ही शिक्षा व स्वास्थ्य की ही मूलभूत सुविधा मौजूद है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में बूथ से लेकर प्रदेश तक 2015-17 तक यहां के कार्यकर्ताओं ने कठिन संघर्ष किया है, इसके बेहतर परिणाम भी मिलने लगे हैं, मैं ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष एवं संगठन की पूरी टीम को ह्रदय से बधाई देता हूं।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आज देश के 17 प्रदेशों में भाजपा एवं भाजपा गठबंधन की सरकारें हैं, 300 से अधिक सांसद हैं, 1700 से अधिक विधायक हैं, देश की लगभग 60% आबादी और 70% भू-भाग पर हम सरकार में रहकर जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें संगठन के विस्तार और विकास के लिए अहर्निश काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केरल, बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना और नार्थ-ईस्ट के राज्यों में भी हमें पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए हमने कई इनिशिएटिव लिए हैं और वहां की एक-एक जनता ने इसे ह्रदय से स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि हमारा पुरुषार्थ जब जनादेश में परिवर्तित होती है, तभी इसे सफलता की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने कहा कि जहां हम चूक गए हैं, वहां हम और मजबूती के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पहुंचें, चारों तरफ कमल ही कमल दिखाई दे। उन्होंने कहा कि हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल देश के विकास के लिए काम करेगी और भारत को एक बार फिर से 'विश्वगुरु' के पद पर प्रतिष्ठित करने का काम करेगी। ■

गरीब जनता के मानस में मोदीजी के प्रति श्रद्धा, आदर और विश्वास का भाव मजबूत हुआ है

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रस्ताव क्रमांक-1 प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सत्यपाल मलिक ने किया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक काम कर रही है। गरीब कल्याण को समर्पित उनकी नीतियों के कारण देश की गरीब जनता के मानस में उनके प्रति श्रद्धा, आदर और विश्वास का भाव न सिर्फ मजबूत हुआ है, बल्कि जनादेश की कसौटी पर प्रमाणित भी हुआ है।

इस प्रस्ताव में सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि सभी मिलकर पंडित दीनदयाल जन्मशताब्दी वर्ष में यह संकल्प लें की जनसेवा के द्वारा जन विश्वास हासिल करने में कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे।

हम प्रस्ताव क्रमांक-1 का पूरा पाठ यहां प्रकाशित कर रहे हैं-

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल में लोक कल्याण हेतु लिए गए निर्णयों ने आर्थिक विकास, राजनीतिक विश्वास, उन्नतिशील भारत के निर्माण एवं वैश्विक पटल पर भारत की साख में मजबूती के लक्ष्यों को हासिल किया है। शासन की नीतियों से समाज के अंतिम छोर पर खड़े आम व्यक्ति की आशाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सफलता पूर्वक काम कर रही है। गरीब कल्याण को समर्पित उनकी नीतियों के कारण देश की गरीब जनता के मानस में उनके प्रति श्रद्धा, आदर और विश्वास का भाव न सिर्फ मजबूत हुआ है, बल्कि जनादेश की कसौटी पर प्रमाणित भी हुआ है। देश के बहुमुखी विकास के लिए अनिवार्य हर जरूरत को वरीयता देते हुए सरकार ने अभूतपूर्व ढंग से काम किया है।

आर्थिक विकास के मोर्चे पर सरकार के प्रयासों से जीएसटी पारित कराने की सफलता मिली तो वहीं बजट को अनुशासन के दायरे में लाते हुए इसके कार्यान्वयन के माध्यम से अर्थव्यवस्था की रफ़्तार को त्वरित रूप से गति प्रदान करने का कार्य हुआ है। तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की हैं, जो भारत को संचार एवं रक्षा क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने की दिशा में उपलब्धि है। निर्माण क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी और विविध क्षेत्रों में मेक इन इण्डिया स्कीम के तहत हासिल हुई आत्मनिर्भरता से भारत विश्व के अग्रणी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में मजबूती के साथ खड़ा नजर आ रहा है।

जनादेश की कसौटी पर खरी सरकार

पांच राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनावों के परिणामों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आजादी के बाद के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में प्रस्थापित किया है। ऐसे समय में जब भाजपा अपने विचारों

के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी को गरीब कल्याण वर्ष के तौर पर मना रही है, इन चुनावों में मिले जनादेश का महत्व बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में पार्टी को विधानसभा चुनावों में और महाराष्ट्र, गुजरात एवं ओड़िसा के निकाय चुनावों में मिली सफलता भाजपा सरकार की गरीब कल्याण को समर्पित नीतियों के प्रति आम जनमानस के अगाध विश्वास की जीत है।

पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की कुशल संगठनात्मक रणनीति एवं संगठन के सभी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का भी अभिनन्दन करती है जिसके कारण पार्टी को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में तीन चौथाई से भी ज्यादा सीटें प्राप्त हुयी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में पार्टी को 2012 विधानसभा चुनाव की तुलना में भारी बढ़ोतरी मिली है। पार्टी को 41(राजग) फीसद वोट और 325 सीटों पर जीत मिली है। यह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। उत्तर प्रदेश की यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में सभी वर्गों एवं सभी क्षेत्रों का व्यापक प्रतिनिधित्व समाहित है। अमीर-गरीब, शहरी-ग्रामीण, अगड़ा-पिछड़ा, युवा, महिला, किसान सभी का प्रतिनिधित्व भाजपा की व्यापक पहुंच को प्रदर्शित करती है। उत्तराखंड में भी भाजपा को ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को 46.5 फीसद वोट मिले हैं एवं कुल 70 में से 57सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। यहां भी भारतीय जनता पार्टी को तीन चौथाई से अधिक के बहुमत का जनादेश मिला है। मणिपुर में भाजपा को मिली सफलता यह प्रमाणित करने के लिए प्रयाप्त है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके शासन की नीतियों की पहुंच देश के उन हिस्सों में भी व्यापक तौर पर हुई है, जहां भाजपा की स्थिति न के बराबर होती थी। मणिपुर विधानसभा चुनाव परिणाम इसका ताजा प्रमाण है। मणिपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा 2.1 फीसद वोट मिले थे और वहां की विधानसभा में भाजपा का प्रतिनिधित्व शून्य था। लेकिन विधानसभा चुनाव 2017 में अभूतपूर्व ढंग से भाजपा को 36.3 फीसद वोट मिले और 21 सीटों पर जीत हासिल हुई। वर्तमान में मणिपुर में भाजपा गठबंधन की सरकार है। गोवा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र निगम चुनावों में नौ महानगरपालिकाओं में से आठ में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली एवं मुंबई महानगर पालिका में भी भाजपा ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 82 सीटों पर जीत दर्ज की। ओडिसा में हुए पंचायत चुनावों भाजपा ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए प्रमुख विपक्षी दल के रूप में अपनी मजबूत स्थिति को कायम किया। यहां पर भाजपा ने कालाहांडी की सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। राजस्थान, दिल्ली, मध्यप्रदेश, हिमाचल, आसाम में हुए विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी मिली जीत से हमारी विश्वास को और मजबूती मिली है। इन उपचुनाव में भी बंगाल में पार्टी की मत प्रतिशत में बढ़ोतरी पार्टी के विस्तार के लिए सुखद है।

भाजपा के प्रति देश के कोने-कोने में जागृत हो रहा यह विश्वास केंद्र सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यपद्धति के प्रति विश्वास का प्रतिफल है। नोटबंदी के बाद हुए इन सभी चुनावों में मिले जनादेश को भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पांच सौ और एक हजार के पुराने नोट बंद किए जाने के फैसले को मिले जनता के समर्थन के तौर पर भी देखती है। 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन घटक दलों के मुख्यमंत्री हैं। सांसदों के साथ-साथ अब विधायक भी सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के हैं।

राजग के 33 दलों के साथ भाजपा का विकास संकल्प

भारतीय जनता पार्टी की विकास परक नीतियों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 33 दलों का साथ मिल रहा है। 33 दलों का यह गठबंधन भाजपा के विकास संकल्प की यात्रा में सहभागी है। देश के हर राज्य, हर क्षेत्र एवं हर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों की भागीदारी वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी एकजुटता के साथ काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्यों में जहां जिस दल के साथ गठबंधन में है, उन्हें शासन में सहभागी बनाकर चलने की नीति का अनुपालन कर रही है। जहां भाजपा की अकेले की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, उन राज्यों में भी राज्यों के राजग के सहभागी दलों को सरकार का हिस्सा बनाकर भाजपा आगे बढ़ रही है। तमिलनाडु, केरल एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में एनडीए के सहयोगी दलों की संख्या व

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में पार्टी को 2012 विधानसभा चुनाव की तुलना में भारी बढ़ोतरी मिली है। पार्टी को 41 (राजग) फीसद वोट और 325 सीटों पर जीत मिली है। यह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। उत्तर प्रदेश की यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में सभी वर्गों एवं सभी क्षेत्रों का व्यापक प्रतिनिधित्व समाहित है।

ताकत में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत के राजनीतिक इतिहास में प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह पहली बार हुआ है कि देश में पूरी निष्ठा से यह गठबंधन काम कर रहा है।

तीन वर्षों में गरीब कल्याण योजनाओं का सफल क्रियान्वयन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेकर आम जन जीवन के हितों में जो तमाम योजनाएं शुरू की गयीं और उन योजनाओं के माध्यम से बदलाव को जमीन पर उतारा गया, यह विजय यात्रा उन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का प्रमाण है। भाजपानीत केंद्र सरकार ने जनधन योजना के अंतर्गत 27.97 करोड़ खाते खोलने का काम करके देश के उन लोगों को मुख्यधारा के अर्थतंत्र से जोड़ने का काम किया है, जो आजादी के पिछले सात दशकों में नहीं हो पाया था। इस योजना के तहत 63,885 करोड़ रुपये इन खातों में जमा हुए। सरकार ने रोजगार और स्टार्टअप एवं स्टैंडअप योजना के तहत रोजगार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के माध्यम से 6.6 करोड़ ऋण दिए। समाज के अंतिम छोर पर जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना एक तहत लगभग 2 करोड़ मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए हैं। विद्युतीकरण के क्षेत्र भाजपानीत केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व ढंग से काम किया है। आजादी के सात दशकों बीतने के बावजूद देश के 18 हजार से ज्यादा गांव ऐसे थे, जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था। सरकार ने 2018 तक सभी गांवों में बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लक्ष्य के तहत काम करते हुए अभी तक 12586 गांवों को बिजली से जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। सरकार की उजाला LED योजना के तहत 11.8 करोड़ lEDबल्ब वितरित किए गए जिससे 11330 करोड़ की बचत हुई। सरकार ने विशेष कर तटवर्ती क्षेत्र के मछुआरों के लिए विशेष ध्यान दिया है। किसानों को फसल बीमा, मृदा स्वास्थ व प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से सीधा लाभ पहुंचाया है। सरकार ने शत्रु संपत्ति विधेयक पारित कराने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोक कल्याण को समर्पित योजनाओं के प्रतिफल में पार्टी जनादेश की कसौटी पर खरी उतरी है।

अर्थतंत्र में सुदृढ़ता से विकास को रफ्तार

जीएसटी पर सफलताः भारतीय जनता पार्टी जीएसटी पर मिली सफलता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को बधाई देती है। सामान और सेवा पर समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को लागू कराने में मिली सफलता ऐतिहासिक है। इससे भारतीय अर्थतंत्र में आने वाली बाधाएं कम होंगी एवं अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। व्यापारिक सुगमता की दृष्टि से जीएसटी का लागू होना एक महत्वपूर्ण सफलता है। इसका सकारात्मक प्रभाव आम व्यक्ति पर पड़ेगा और व्यापार क्षेत्र में तेजी आएगी जिससे रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। जीएसटी के कारण महंगाई में भी कमी आएगी। आर्थिक सुधारों की दृष्टि से जीएसटी को पारित कराना भाजपानीत केंद्र सरकार की उपलब्धि है।

बजट 2017-18 : भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2017-18की सराहना करती है। यह बजट लोक कल्याण की मूल भावना का प्रतिबिंब होने के साथ-साथ आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने में भी सक्षम है। एक राष्ट्र एक बजट की तर्ज पर इस बार केंद्र सरकार ने रेल बजट को अलग से पेश करने की बजाय आम बजट के साथ ही पेश किया। सरकार द्वारा पहली बार अनुशासन के दायरे में 1 फरवरी को बजट पेश होने से बजट वितरण एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आई है। रोजगार गारंटी के तहत खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस बजट के माध्यम से मनरेगा के लिए 11000 करोड़ की बढ़ोतरी करके 48000 करोड़ कर दिया गया है। निम्न मध्यम वर्ग को आयकर स्लैब्स में छूट देने का सरकार का निर्णय सराहनीय है। कुल 21.47 लाख करोड़ के बजट में गरीब, मजदूर, दिव्यांग, महिला, बाल विकास, निर्माण क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, बीमा सुरक्षा सहित प्रत्येक मुद्दे को बारीकी से वरीयता दी गयी है। रक्षा क्षेत्र के लिए बजट से 2.74 लाख करोड़, बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 3.96 लाख करोड़, हाइवे विकास के लिए 64000 करोड़, महिला कल्याण फंड के तहत 1.86 लाख करोड़, रेल सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त इस बजट के तहत जन सरोकार से जुड़े अन्य तमाम लक्ष्यों जैसे- 1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली की उपलब्धता, किसानों को 10 लाख करोड़ कर्ज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2019 तक 1 करोड़ परिवारों को आवास, महात्मा गांधी की 150वी जयंती तक 1 करोड़ गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने जैसे तमाम लोक कल्याण को समर्पित लक्ष्य चिन्हित किए गए हैं। यह बजट केंद्र सरकार के लोक कल्याण के प्रति समर्पण को दिखाता है तो वहीं दूसरी तरफ विकास एवं आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के प्रति संकल्पित नजर आता है। आजादी के बाद पहली बार

एक राष्ट्र एक बजट की तर्ज पर इस बार केंद्र सरकार ने रेल बजट को अलग से पेश करने की बजाय आम बजट के साथ ही पेश किया। सरकार द्वारा पहली बार अनुशासन के दायरे में 1 फरवरी को बजट पेश होने से बजट वितरण एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आई है।

बजट को 31 मार्च से पहले पारित करके कियान्वित भी कर दिया है। जो देश के वित्तीय अनुशासन एवं आर्थिक विकास में बहुत बड़ा कदम है।

चुनाव सुधार और चंदे में पारदर्शिता: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस दिशा में ठोस पहल करते हुए राजनीतिक दलों के चंदे की नकदी सीमा को 20000 रुपए से कम करते हुए 2000 तक कर दिया। केंद्र सरकार का यह कदम चुनाव सुधार एवं चंदे में पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम है।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम

भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की पुरजोर पक्षधर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इस लक्ष्य को मजबूती से हासिल करते हुए, 1 मार्च 2017 को स्वदेश निर्मित सुपरसोनिक इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया गया।

अन्तरिक्ष में भारत की धमक:

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इसरो ने विश्व में पहली बार एक साथ 104 उपग्रहों का अन्तरिक्ष में सफल प्रक्षेपण करने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इसके पहले रूस ने 37 उपग्रह छोड़े थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ाने की दिशा में लगातार किया जा रहा उनका प्रयास गौरवान्वित करने वाला है। एक दौर था जब इस कार्य के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन आत्मनिर्भरता का संकल्प लेकर काम कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आत्मनिर्भरता की ओर मजबूत कदम रख दिया है और इसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व बधाई के योग्य है।

भीम एप: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से ही डिजिटल इण्डिया को लेकर व्यापक स्तर पर काम हुए हैं। नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भीम एप लांच किया जो कि काफी लोकप्रिय हो चुका है। शुरू के दौर में ही इस एप को इस्तेमाल करने वालों की संख्या सवा करोड़ से ज्यादा हो गयी थी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति:

भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 प्रस्तावित करने एवं इसे मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद को बधाई देती है। केंद्र सरकार ने इस स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत दुर्गम बीमारियों को मुफ्त सरकारी सुविधा, दवा एवं जांच को सस्ता एवं सुलभ करना, आयुष को मुख्यधारा में जोड़ना, बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ के सम्बंधित सभी सुविधाओं को सस्ता करके गरीबों तक उपलब्ध कराना जैसे लक्ष्यों के साथ एक व्यापक, समावेशी एवं समय के जरूरतों के हिसाब से इस नीति को तैयार किया है। अत्याधुनिक तकनीक के साथ-साथ परंपरागत प्रणालियों से सज्ज राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 स्वस्थ भारत बनाने की दिशा में अचूक कार्यक्रम साबित होगी।

वैश्विक पटल पर चमकी भारत की साख

वर्ष में 2014 में भाजपा की सरकार आने और श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही विश्व जगत में भारत की साख ऊंची हुई है। दुनिया की निगाहें अब भारत की ओर हैं। तमाम आंकड़े भारत को एक संभावनाओं का देश मानने लगे हैं। दुनिया के तमाम देशों से भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं। व्यापारिक, सामरिक एवं कूटनीतिक स्तर पर भारत की ताकत और साख में इजाफा हुआ है। इसकी एकमात्र वजह यह है कि वर्तमान में देश में एक मजबूत सरकार है जिसका नेतृत्व एक मजबूत नेता के हाथों में है। विश्व पटल पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रशासकीय कार्यशैली, लोक कल्याण को समर्पित नीतियों, मजबूत इच्छाशक्ति, सशक्त नेतृत्व की असीम क्षमता को पुरजोर स्वीकृति मिली है।

भारतीय जनता पार्टी सांसदों को 2014 में संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित पहली संसदीय बैठक को संबोधित करते हुए एवं दायित्व बोध का एहसास कराते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा था कि "हम पद के लिए नहीं अपितु 125 करोड़ लोगों की आशा और आंकझाओं को पूरा करने के लिए समेट कर बैठे है, इसलिए पदभार जीवन में बहुत बड़ी बात होती है यह मैंने कभी नहीं माना, लेकिन कार्यभार, जिम्मेवारी ये सबसे बड़ी बात होती है। हमें उसे परिपूर्ण करने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा।" माननीय प्रधानमंत्री जी के इन तीन वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने अपनी कर्मठता से अपने इस शब्दों को जनता के विश्वास में बदल दिया है। यह कार्यकारिणी अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करती है कि सभी मिलकर पंडित दीनदयाल जन्मशताब्दी वर्ष में यह संकल्प लें की जनसेवा के द्वारा जन विश्वास हासिल करने में कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश के जनता से भी आह्वान करती है कि देश में विकास एवं गरीब कल्याण कार्यक्रमों की निरंतरता हेतु 2019 के चुनावों में भी श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने हेतु संकल्पवान हो। ■

दुनिया की निगाहें अब भारत की ओर हैं। तमाम आंकड़े भारत को एक संभावनाओं का देश मानने लगे हैं। दुनिया के तमाम देशों से भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं। व्यापारिक, सामरिक एवं कूटनीतिक स्तर पर भारत की ताकत और साख में इजाफा हुआ है।

राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का फैसला

एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और अभूतपूर्व निर्णय

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद श्री हुकुमदेव नारायण यादव ने प्रस्ताव क्रमांक-2 रखा, जिसका अनुमोदन झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास ने किया। इस प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के फैसले का स्वागत और अभिन्दन किया है और कहा गया है कि आजादी के 70 साल बाद किसी सरकार द्वारा समाज के गरीब, दूर-दराज के क्षेत्रों में जीवन यापन कर रहे पिछड़ा समाज के हितों में लिया गया यह एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और अभूतपूर्व निर्णय है। समाज के कमजोर वर्गों की न्याय देने के लिए लम्बे समय से अपेक्षित मांग को पूरा किया गया है।

प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक संस्थाओं से आह्वान किया है कि समतामूलक समाज के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक फैसले के महत्व को दूरस्थ क्षेत्रों के गरीब एवं पिछड़े वर्गों तक पहुंचाएं। हम यहां प्रस्ताव क्रमांक-2 का पूरा पाठ यहां प्रकाशित कर रहे हैं-

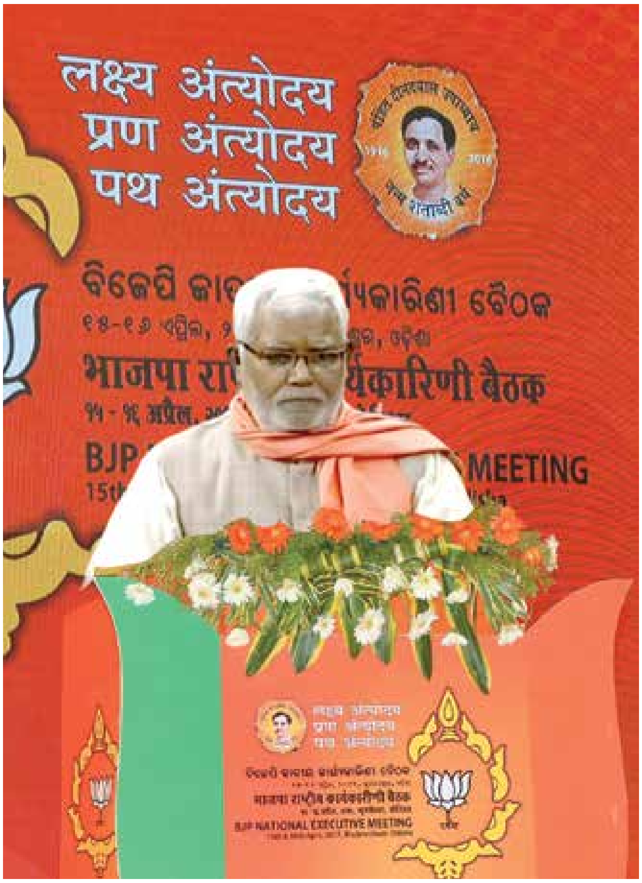

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए लोकसभा में अपने पहले भाषण में कहा था, "हम तो पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के आदर्शों से पले हुए लोग हैं। जिन्होंने हमें अन्त्योदय की शिक्षा दी थी। गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दें। शासन की सारी व्यवस्थायें गरीब को सशक्त बनाने के लिए काम आनी चाहिए और सारी व्यवस्थाओं का अंतिम नतीजा उस आखिरी छोर पर बैठे हुए इन्सान के लिए काम आए, उस दिशा में प्रयास होगा, तब जाकर उसका कल्याण हम कर पाएंगे।" माननीय प्रधानमंत्री जी के अपने पहले संबोधन पर प्रतिबद्धता के साथ तीन साल के शासनकाल में मजबूती से इस दिशा में कदम बढ़ाये है।

भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के फैसले का स्वागत और अभिनन्दन करती है।

आजादी के 70 साल बाद किसी सरकार द्वारा समाज के गरीब दूर-दराज के क्षेत्रों में जीवन यापन कर रहे पिछड़ा समाज के हितों में लिया गया एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और अभूतपूर्व निर्णय है। समाज के कमजोर वर्गों को न्याय देने के लिए लम्बे समय से अपेक्षित मांग को पूरा किया गया है।

इस ऐतिहासिक कदम के लाभ:

इस ऐतिहासिक फैसले से समाज के सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय मिलेगा। मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग एक साधारण क़ानूनी निकाय है, जिसका कार्य सरकार को जातियों/समुदायों की सूचियों में शामिल करने अथवा निकालने के संबंध में सलाह देना है। अब इस आयोग को सांविधिक निकाय के रूप में एनसीएससी और एनसीएसटी के बराबर का दर्जा मिल जायेगा। यह आयोग पिछड़ा वर्ग के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नति से संबंधित अन्य कार्यों का भी निर्वहन करेगा। यह आयोग संविधान के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 16-4 एवं 15-4 के निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को सशक्त करते हुए उनको न्याय देगा।

समतामूलक समाज निर्माण का लक्ष्य भाजपा की प्रतिबद्धता रही है और भाजपा सरकार ने इस फैसले से उस दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है। एक न्यायपूर्ण भारत और समतामूलक समाज की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की क्षमता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिए गए इस अहम निर्णय में अंतर्निहित है।

कांग्रेस और क्षेत्रीय विपक्षी दलों का पिछड़ा वर्ग विरोधी आचरण:

आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा-नीत सरकार ने समाज के पिछड़े वर्ग के हितों को समर्पित वर्षों से लंबित इस कार्य को किया है तो ऐसे में कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों का रुख बेहद निराशाजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस एवं विपक्षी दलों ने जिस तरह से राज्यसभा में इसका विरोध किया है, पिछड़े वर्ग को लेकर उसकी मूल मनोस्थिति को दिखाता है। यह सच है कि देश में लंवे समय तक शासन में रहने के बावजूद कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के हितों का यह काम नहीं कर पाई। अब जब भाजपा को शासन का जनादेश मिला है तो भाजपा की सरकार ने वरीयता में रखकर इस कार्य को किया है। आजादी के बाद काका कालेकर कमीशन (1950) और मंडल आयोग (1979) की रिपोर्ट के बावजूद भी तत्कालीन कांग्रेस की सरकारों द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। विदित है कि इस अहम निर्णय को लागू करने के संबंध में ओबीसी संसदीय समिति की सिफारिश भी आई और सभी दलों के सांसदों ने व्यक्तिगत रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाक़ात करके इस संबंध में संविधान में संशोधन करने का आग्रह किया था। इस दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए इसे लोकसभा में सर्वसम्मति पारित भी करा लिया। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के पिछड़े तबके के लोगों को सशक्त बनाने और उन्हें न्यायिक रूप से और मजबूत करने की दिशा में उठाए गए इस कदम को राज्यसभा में विरोध करके रोक दिया गया है। राजनीति में राजनीतिक विरोध चलते हैं, आरोप-प्रत्यारोप भी होते हैं, लेकिन गरीब और हाशिये के समाज के लिए हो रहे किसी फैसले को अपनी राजनीति के लिए रोकना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस एवं विपक्षी दलों द्वारा राजनीति में सिर्फ इस बात के लिए इस निर्णय का विरोध करना उचित नहीं कहा जा सकता है कि अमुक काम लंबे समय तक शासन में रहने के बावजूद वे इस काम को नहीं कर पाए और भाजपा की सरकार ने कर दिया। एक ओर कांग्रेस व विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया वही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाहजी के नेतृत्व में सभी एनडीए दलों एवं मुख्यमंत्रियों ने इसको समर्थन देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया।

पार्टी के सभी नेताओं को गरीब वर्गों के संवैधानिक एवं क़ानूनी अधिकारों के जागरण का प्रयास करना चाहिए और इसके साथ-साथ विपक्षी दलों के पिछड़ा वर्ग विरोधी आचरण का पर्दाफाश भी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को दिए गये इस ऐतिहासिक संवैधानिक अधिकार पर माननीय प्रधानमंत्री जी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है।

भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक संस्थाओं से आह्वान करती है कि समतामूलक समाज के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक फैसले के महत्त्व को दूरस्थ क्षेत्रों के गरीब एवं पिछड़े वर्गों तक पहुंचाएं। पार्टी के सभी नेताओं को गरीब वर्गों के संवैधानिक एवं क़ानूनी अधिकारों के जागरण का प्रयास करना चाहिए और इसके साथ-साथ विपक्षी दलों के पिछड़ा वर्ग विरोधी आचरण का पर्दाफाश भी करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गरीबों को दिए गये इस ऐतिहासिक संवैधानिक अधिकार पर माननीय प्रधानमंत्री जी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। ■

विकास के साथ-साथ सुशासन बहुत जरूरी है : नरेन्द्र मोदी

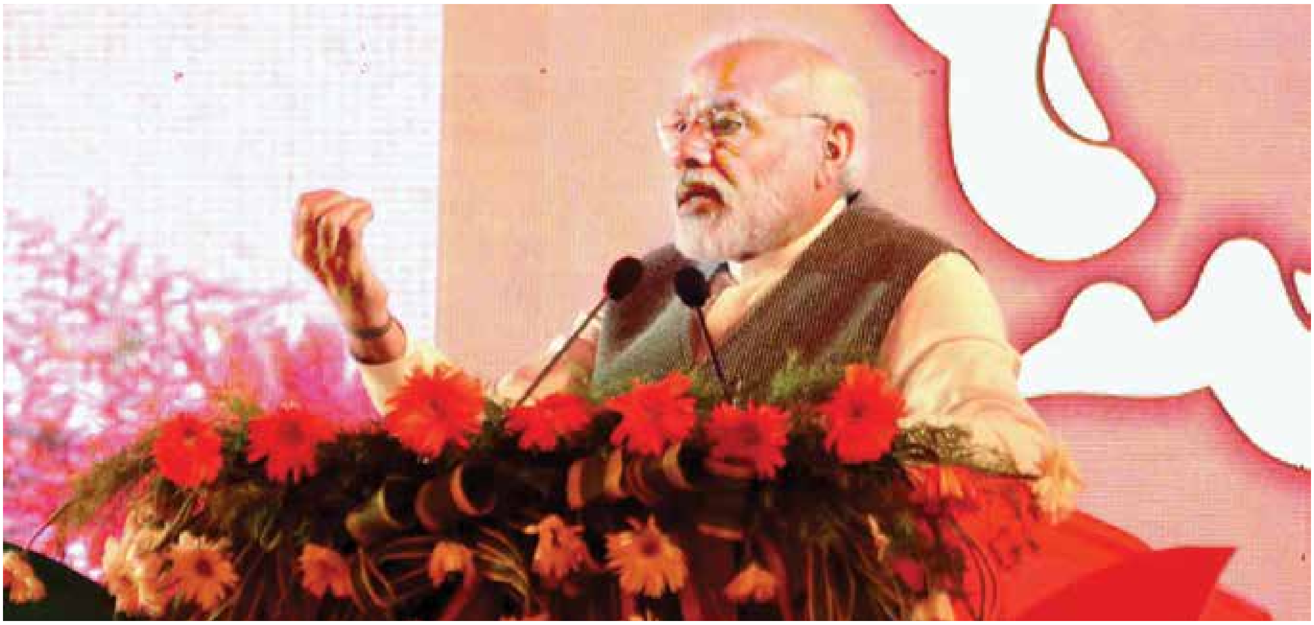

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भुवनेश्वर के जनता मैदान में भगवान जगन्नाथ की पावन धरती पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के समापन सत्र को संबोधित किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से देश एवं समाज के विकास के लिए कृतसंकल्पित होने का आह्वान किया। उन्होंने इतने कम समय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के सफल आयोजन के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओडिशा इकाई की पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ओडिशा में पार्टी मजबूत हुई है, पार्टी में गुणात्मक परिवर्तन आया है और वह दिन दूर नहीं जब भाजपा की ओडिशा इकाई देश भर में पार्टी की राज्य इकाइयों की प्रेरणा का केंद्र बनेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यू इंडिया के विजन को चरितार्थ करने वाली राजनीतिक दृष्टि और उसे परिपूर्ण करने के लिए तीन वर्ष में लगातार हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कृतित्व के द्वारा हर कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने कहा कि जब हम कहते हैं 'सबका साथ, सबका विकास' तो इसका मतलब यह है कि हमारे हर कार्य के अंदर, हमारी हर नीति के मूलमंत्र में यह निहित है और हमारे हर निर्णयों में यह परिलक्षित भी होता है।

श्री मोदी ने कहा कि हमारे लिए सत्ता साध्य नहीं, साधन है जिसके माध्यम से हमें देश को विकास की एक नई ऊंचाई पर प्रतिष्ठित करना है, हमारे लिए राजनीति जनता की सेवा का एक मंच है। उन्होंने कहा कि जय और पराजय हमारे जनसेवा और देश सेवा के मिशन को कभी चुनौती पेश नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम वे लोग हैं जो जय-

भारतीय जनता पार्टी अपने कृतित्व के द्वारा हर कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने कहा कि जब हम कहते हैं 'सबका साथ, सबका विकास' तो इसका मतलब यह है कि हमारे हर कार्य के अंदर, हमारी हर नीति के मूलमंत्र में यह निहित है और हमारे हर निर्णयों में यह परिलक्षित भी होता है।

पराजय को आत्मसात कर उसे खाद के रूप में उपयोग कर और अधिक निखर कर उभरे हैं और आगे बढ़े हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कोटि-कोटि जन हमें सिर्फ विजयी देखना ही नहीं चाहते बल्कि वे हमसे अपनापन भी महसूस करते हैं, ऐसे

में हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमारा हर कार्य उनकी भलाई के लिए ही केन्द्रित हो। उन्होंने कहा कि आज ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा है जिस पर विरोधी दल हमारे संगठन अथवा सरकार को कठघरे में खड़ा कर सके। उन्होंने कहा कि लोगों को इस बात का भरोसा है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं और न ही गलत इरादे से कोई काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास हमारी पूंजी है, जनता का विकास हमारा मकसद है और गरीब कल्याण ही हमारे जीवन का ध्येय है। हम इस मूलमंत्र पर जितना ध्यान केन्द्रित करेंगे, परिणाम उतने ही अच्छे आयेंगे।

श्री मोदी ने कहा कि संगठन ने काफी अच्छी कार्य-योजना बनाई है और देश के हर कोने में पार्टी का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, अगर हम उनकी बनाई गई कार्य-योजनाओं पर अमल करें तो हर बूथ पर कमल खिल सकता है।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए नए नए इश्यूज क्रियेट किये जा रहे हैं, जब से हमारी सरकार केंद्र में आई है, इश्यूज मैनूफैक्चर किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे से हमारा दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं होता, उस मुद्दे को भी हमसे जोड़ कर विवाद खड़े करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चर्चों पर हमले का विवाद खड़ा किया गया, लेकिन जब जांच हुई और सच्चाई सामने आई तो विरोधियों की पोल खुल गई, फिर चुनावों में लाभ के लिए अकारण अवार्ड वापसी का ड्रामा किया गया, पता नहीं अब वे अवार्ड वापसी वाले कहां चले गए और अब ईवीएम का नया इश्यू मैनूफैक्चर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सच्चाई सबको मालूम है लेकिन फिर भी देश में झूठ चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गर्मागर्म और सनसनी वाले चीजों से टीवी और मीडिया में तो जगह मिल सकती है, लेकिन वे देश की जनता के दिल में जगह कभी नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि हम सत्यनिष्ठा से देश के गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, युवा एवं महिलाओं की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और उनके जीवन-स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम गरीब कल्याण की योजनाओं को विकास की दौड़ में पिछड़ गए समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हुए हैं।

संगठन ने काफी अच्छी कार्य-योजना बनाई है और देश के हर कोने में पार्टी का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, अगर हम उनकी बनाई गई कार्य-योजनाओं पर अमल करें तो हर बूथ पर कमल खिल सकता है।

श्री मोदी ने कहा कि यह हमारा दायित्व बनता है और यह हमारा संस्कार भी है कि समाज का कोई वर्ग हमसे अलग महसूस नहीं करे। उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ सुशासन बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट प्लस गुड गवर्नेंस हमारा सिद्धांत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस का मेरा मंत्र है – P2G2, इसका मतलब है "pro-people pro-active good governance"।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तब क्या हम 125 करोड़ लोगों को देश के लिए, देश के विकास के लिए एक साथ कर्त्तव्य पथ पर अग्रसर कर सकते हैं, इस तरह का प्रयास किया जाना चाहिए, अभी इसके लिए हमारे पास पांच वर्षों का समय है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें वर्षगांठ को हम एक लक्ष्य के रूप में सामने रख कर देश के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प लें। हम हर हिन्दुस्तानी इसे अपने कर्त्तव्य-पथ का उत्सव समझें, इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाएं और इस बात का संकल्प लें कि देश में एक भी व्यक्ति गरीब न रहे।

श्री मोदी ने कहा कि हमें तीन विषयों पर ध्यान देना चाहिए – जन-धन, वन-धन और जल-धन, इन तीनों धन को सिंचित और संरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया कंसेप्ट की सोच को नई पीढ़ी तक ले जाने के लिए हमें अभी से जुट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश का अमीर तबका भी यह मानता है कि डिमोनेटाइजेशन से ईमानदारी के साथ जीने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा हर काम ईमानदारी का होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए और ईमानदारों को पुरस्कृत करने का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हम दीया जलाते हैं तो अंधेरा अपने-आप ही छंटेगा। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया का कंसेप्ट यही है कि एक ऐसे देश का निर्माण जहां परिश्रम की पूजा हो, ईमानदारी की पूजा हो, समाज में ऊंच-नीच का भाव न हो, योजनाओं में छोटे से छोटे व्यक्ति का हिस्सा हो, टेक्नोलोजी से एम्पावर्ड हो, सबका साथ हो – सबका विकास हो। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक का सपना न्यू इंडिया होना चाहिए। ■

सेवा यात्रा के इस यज्ञ ने पूरे मध्य प्रदेश को एकजुट करने का काम किया है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने जबलपुर (मध्य प्रदेश) में आयोजित नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा में भाग लिया और इस अवसर पर आयोजित एक विशाल कार्यक्रम को भी संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करने के पश्चात वे मां नर्मदा की महा-आरती में भी शामिल हुए और पर्यावरण, संस्कृति एवं धर्म के ध्वज को हाथों में लेकर नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा के सहभागी बने। कन्या-पूजन के साथ-साथ उन्होंने संतों का सान्निध्य एवं आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस सेवा यात्रा में देश भर से आये संतों के साथ विशाल संख्या में जनमानस भी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अगुआई में मां नर्मदा के संरक्षण का संकल्प लेने शामिल हुए। इस कार्यक्रम में यूएनओ के प्रतिनिधि भी विशेष रूप से उपस्थित थे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जीवनदायिनी मां नर्मदा को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए श्री शिवराज जी ने जो भगीरथ पुरुषार्थ किया है, वह अपने आप में अप्रतिम है। उन्होंने कहा कि गुजरात को भी सुजलाम-सुफलाम बनाने में मां नर्मदा के प्रताप का ही योगदान है। उन्होंने कहा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ-साथ राजस्थान भी मां नर्मदा के आशीर्वाद से जगमग कर रहा है। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा के लगभग 1200 किमी का पवित्र प्रवाह इन राज्यों में लोगों के जीवन का मूल कारण बना है।

श्री शाह ने कहा कि मां नर्मदा जीवनदायिनी तो है ही, साथ ही यह मोक्षदायिनी भी है। उन्होंने कहा कि पुराणों व उपनिषदों में मां नर्मदा की महिमा का विशेष रूप से बखान किया गया है, पुराणों में कहा गया है कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा के किनारे ही सनातन धर्म की सेवा का बहुत बड़ा यज्ञ ऋषि-मुनियों ने शुरू किया था। उन्होंने कहा कि जब सनातन धर्म पर सबसे बड़ा संकट आया तो आदिगुरु शंकराचार्य ने मां नर्मदा के तट पर ही सनातन धर्म की रक्षा करने और उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाने का बीड़ा उठाया था, मां नर्मदा भारत की संस्कृति और धर्म की प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शिवराज जी मां नर्मदा के तट पर स्थित आदिगुरु शंकराचार्य की गुफा को भी अच्छे से बना कर एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मां नर्मदा को संरक्षित करने का अभियान प्रारंभ करके श्री शिवराज जी ने आधुनिक भगीरथ का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में साबरमती और सरस्वती नदी के साथ-साथ 21 नदियों में मां नर्मदा का पानी डाल कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे गुजरात की नदियों को सजीवन करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि कभी इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन पेड़ों के अत्यधिक कटाव से भू-क्षरण और पर्यावरण असंतुलन के कारण कब तक मां नर्मदा लोगों को

जीवन देती रहेगी। उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से मां नर्मदा हमें जीवन देती आई है, अब समय आ गया है कि समाज भी मां नर्मदा के लिए कुछ करे। उन्होंने कहा कि शिवराज जी ने नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा का जो जन-आंदोलन शुरू किया है, उससे पूरे मध्य प्रदेश की जनता जुड़ गई है, सेवा यात्रा के इस यज्ञ ने पूरे मध्य प्रदेश को एकजुट करने का काम किया है।

श्री शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में जब फलदार वृक्ष लगेंगे, नए मुक्तिधाम बनेंगे, मल-मूत्र जब मां नर्मदा में नहीं जाएगा, कारखानों का गंदा पानी मां नर्मदा में नहीं जाएगा, पूजा सामग्री के विसर्जन के लिए जब अलग से कुंड बनेगा, शराब के ठेकेदारों को मां नर्मदा के किनारे से पांच किलोमीटर दूर खदेड़ दिया जाएगा तो इससे न केवल ऊर्जा, रोजगार और अनाज का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि संस्कृति और धर्म भी पुनर्जीवित और संरक्षित होगी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया की कई नदियों को शुद्ध किया गया है, मुझे लगता है कि शिवराज जी ने जो यह अभियान जन-आंदोलन के रूप में शुरू किया है, वह आने वाले दिनों में मां नर्मदा को भी शुद्ध नदी की सूची में जोड़ने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, वह तो केवल एक सिंबल है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुझे विश्वास है कि मां गंगा के शुद्धिकरण का काम भी इतनी ही तेज गति से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मां गंगा, नर्मदा और यमुना जी के शुद्ध हो जाने से देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पहाड़ों, जंगलों एवं नदियों को संरक्षित एवं संवर्द्धित करने के अभियान को जिस तरह से जन-आंदोलनों में परिवर्तित किया है, उसी अभियान को श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया है। ■

भाजपा ने दिल्ली, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और असम में उप-चुनाव की सीटें जीतीं

दिल्ली नगर चुनाव से पूर्व ही भाजपा के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी मतों से जीत प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। भाजपा ने राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव में विजय हासिल कर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से हरा दिया है, जो तीसरे नम्बर तक जा पहुंची और उसने अपनी जमानत भी गंवा दी।

भाजपा ने 9 अप्रैल में हुए उप-चुनावों में 10 सीटों में से 5 सीटों पर जबर्दस्त जीत हासिल की। 13 अप्रैल 2017 को दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, असम और राजस्थान में विधानसभा उपचुनावों में भी जीत हासिल की।

श्रीनगर संसदीय सीट के अलावा आठ राज्यों में 11 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में दो-दो और पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली में प्रत्येक में एक-एक सीट के लिए चुनाव हुए।

दिल्ली नगर चुनाव से पूर्व ही भाजपा के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी मतों से जीत प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। भाजपा ने राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव में विजय हासिल कर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को बुरी तरह से हरा दिया है, जो तीसरे नम्बर तक जा पहुंची और उसने अपनी जमानत भी गंवा दी।

भाजपा-शिअद संयुक्त प्रत्याशी मनजिन्द्र सिंह सिरसा को 40602 वोट मिले, जो डाले गए कुल वाटों का 50 प्रतिशत से अधिक है, अतः यह भाजपा के लिए अत्यंत प्रोत्साहनवर्धक है।

कांग्रेस की मीनाक्षी चंदेला 25,950 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंची, जबकि 'आप' के हरजीत सिंह को केवल 10243 वोट प्राप्त हुए, जो डाले गए कुल वोटों का एक-छहाई से भी कम है।

मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपने विपक्षी कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री सिंह को हरा कर उमरिया से 25476 वोटों से सीट हासिल कर ली।

हिमाचल प्रदेश में भाजपा प्रत्याशी डॉ. अनिल धीमान ने 8290 वोटों से भोरंज (अनु.जाति) विधानसभा सीट जीत ली। भाजपा ने कांग्रेस प्रतिद्वन्द्वी प्रोमिला देवी को 8290 वोटों से हराया।

श्री धीमान को 24453 वोट प्राप्त हुए जबकि देवी को 16144 वोट ही मिल पाए।

@narendramodi

'बीजेपी फॉर इंडिया' और एनडीए की देश के विभिन्न हिस्सों में हुए उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं को बधाई। मैं लोगों को विकास और सुशासन की राजनीति में लगातार समर्थन, आशीर्वाद, दृढ़ विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूं।

@AmitShah

मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को हालिया संपन्न हुए उपचुनावों में भाजपा को प्रमुख विपक्षी दल बनाने के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं।

पार्टी ने असम में भी अच्छा प्रदर्शन किया जहां उसके प्रत्याशी रनोज पेगू ने अपने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बाबुल सोनोवाल को 9285 वोटों से पराजित कर दिया। जहां भाजपा को 75217 वोट मिले, वहीं कांग्रेस को मात्र 65392 वोट ही मिल पाए। राजस्थान में भाजपा उम्मीदवार शोभा रानी ने धौलपुर विधानसभा के उपचुनाव में जीत प्राप्त की। ■

प्रधानमंत्री द्वारा 'आधार' आधारित नया 'भीम' ऐप लॉन्च

भीम–कैशबैक और रैफरल बोनस योजना की भी शुरुआत

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को आधार नंबर से चलने वाला नया "भीम" (बीएचआइएम-भारत इंटरफेस फॉर मनी) ऐप लांच किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, "एक समय था जब लोग अंगूठे के निशान को अनपढ़ होने से जोड़ते थे, लेकिन तकनीक ने आज अंगूठे को ताकत का स्रोत बना दिया है।"

श्री मोदी ने कहा कि लोग अपने फोन पर अंगूठे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी बात है। भीम-आधार ऐप के लिए स्मार्टफोन, इंटरनेट और डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। व्यक्ति का पढ़ा-लिखा होना भी जरूरी नहीं है। किसी भी ग्राहक से पैसा लेने के लिए दुकानदार को उसका आधार नंबर और अंगूठे के निशान की ही जरूरत होगी।

उन्होंने कहा कि भीम-आधार पे ऐप सामान्य भारतीय के सशक्तिकरण में वही भूमिका अदा करेगा जैसी अंबेडकर के बनाए भारतीय संविधान ने की है। इससे बाबा साहब अंबेडकर का सभी के सामाजिक और वित्तीय सशक्तिकरण का सपना पूरा हो सकेगा।

यही नहीं, प्रधानमंत्री ने दो प्रोत्साहन योजनाएं "भीम-कैशबैक" और "रैफरल बोनस" भी शुरू कीं। 495 करोड़ रुपए के बजट से छह महीने के लिए शुरू की गईं इन योजनाओं का उद्देश्य डिजिटल पेमेंट की संस्कृति का जमीनी स्तर तक प्रसार करना है।

मुख्य बातें

- लोगों का मोबाइल फोन ही अब एटीएम बन जाएगा।
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इसे इस प्रकार से डेवलप किया गया है कि आप अपनी उंगलियों के निशान को प्रमाणित करके पैसा निकाल सकेंगे।
- डेबिट-क्रेडिट कार्ड ले जाए बगैर हो सकेगा वित्तीय लेन-देन।
- भीम-आधार ऐप दुनिया में अपनी किस्म का अनोखा है। यहां तक कि दुनिया के सबसे विकसित देशों में भी ऐसा तंत्र नहीं है। यह पूरी तरह से गेमचेंजर साबित होगा।
- दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में भीम-आधार ऐप आने वाले दिनों में रिसर्च का विषय बनेगा।
- रेफरेल बोनस योजना के तहत भीम ऐप यूजर किसी दूसरे स्मार्टफोन उपयोक्ता को इस सुविधा से जोड़ सकता है और एक निश्चित रकम कमा सकता है।
- यदि आप किसी को भीम ऐप से जोड़ते हैं और वह व्यक्ति तीन ट्रांजैक्शन करता है तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। यह स्कीम 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
- अगले दो हफ्ते में इस पर और काम कर लिया जाएगा जिससे भीम ऐप और शक्तिशाली बनकर उभरेगा।

"रैफरल बोनस" योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि यदि आप भीम ऐप से किसी को जोड़ते हैं तो संबंधित व्यक्ति की ओर से तीन ट्रांजैक्शंस किए जाने के बाद आपके खाते में 10 रुपये आ जाएंगे। यह स्कीम इस साल 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी।' श्री मोदी ने कहा कि भीम ऐप को रोका नहीं जा सकता। यदि कैशलेस इकॉनमी एक रथ है तो भीम ऐप उसका सारथी है। इसे रोका नहीं जा सकता।

उन्होंने कहा कि ऐसा दिन आएगा, जब लोगों की जेब में पैसे नहीं होंगे और वह हर जगह आते-जाते दिखेंगे। श्री मोदी ने कहा, 'हम देखते हैं कि एक एटीएम की सुरक्षा में 5 पुलिसकर्मी लगे होते हैं। यदि हम कैश में बहुत ज्यादा डील नहीं करते हैं तो आपका मोबाइल ही एटीएम बन जाएगा। वह दिन ज्यादा दूर नहीं है, जब बैंकों का कोई परिसर नहीं होगा और न ही पेपर होंगे।' साथ ही प्रधानमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और उनकी टीम को दुनिया की श्रेष्ठ पेमेंट टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए बधाई दी।

गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद से डिजिटल लेन-देन की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। मार्च तक देश में 64 लाख से अधिक डिजिटल लेन-देन हो चुके हैं। इनमें करीब 2,425 करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है। मार्च 2017 तक आधार आधारित लेनदेन की संख्या भी नवंबर 2016 के 2.5 करोड़ से बढ़कर पांच करोड़ हो गई है। ■

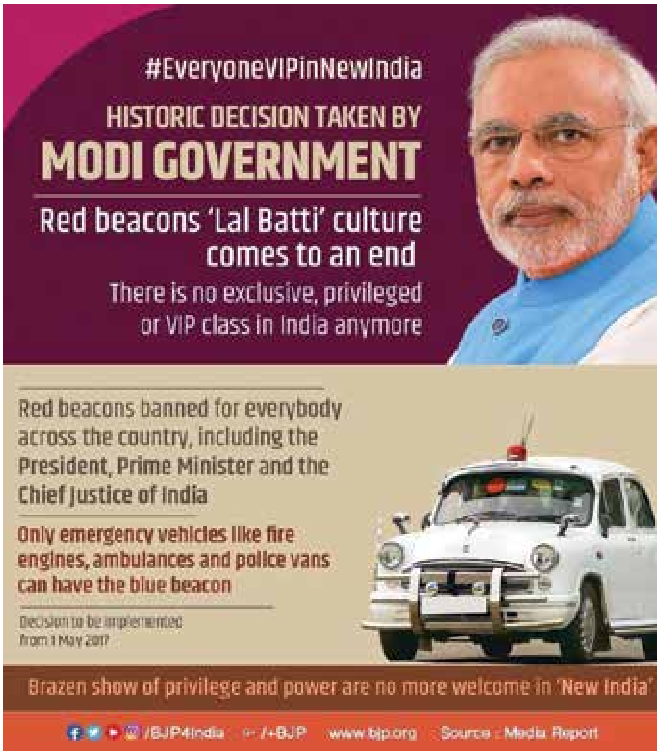

केंद्र सरकार ने सभी श्रेणियों के वाहनों से सभी तरह की बत्तियां हटाने का फैसला लिया

देश में स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल को एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश में सभी श्रेणियों के वाहनों के ऊपर लगी सभी तरह की बत्तियां हटाने का फैसला किया। सरकार का स्पष्ट मानना है कि वाहनों पर लगी बत्तियां वीआईपी संस्कृति का प्रतीक मानी जाती हैं और लोकतांत्रिक देश में इसका कोई स्थान नहीं है। उनका कुछ भी औचित्य नहीं है। हालांकि आपातकालीन और राहत सेवाओं, एम्बुलेंस, अग्नि शमन सेवा आदि से संबंधित वाहनों पर बत्तियों लगाने की अनुमति होगी। इस फैसले को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कानून में आवश्यक प्रावधान करेगा। ■

भारत सरकार की कुछ प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाएं

केंद्रीय सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 15 अप्रैल को भारत सरकार की कुछ प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं की जानकारी दी। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं निम्न हैं...

स्टैंड अप इंडिया योजना

स्टैंड अप इंडिया योजना का लक्ष्य जनसंख्या के वंचित वर्गों तक पहुंचने में संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठाना है। यह कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता को और प्रति बैंक शाखा कम से कम एक महिला कर्जदार को ग्रीन फील्ड उद्यम की स्थापना करने के लिए 7 वर्षों तक भुगतान कर सकने योग्य 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराता है। सिडबी एवं नाबार्ड स्टैंडअप इंडिया के कनेक्ट सेंटर हैं। इस योजना के तहत वित्त के अलावा, अन्य प्रारंभिक सहायता भी प्रदान की जाती है। पोर्टल पर 106358 शाखाओं के साथ 97 बैंक सक्रिय हैं। अभी तक 19949 आवेदनों का आगे बढ़ाया गया है और 4114 करोड़ रुपये संवितरित

किये गये हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अंतिम पायदान पर खड़े वित्त पोषकों के पुनर्वित्त का कार्य मुद्रा कंपनी द्वारा किया जाता है। मुद्रा कंपनी विनिर्माण, व्यापार एवं सेवा कार्यकलापों से जुड़ी सूक्ष्म एवं लघु व्यावसायिक कंपनियों को ऋण देने से संबंधित सिडबी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इस योजना के तहत दिया जाने वाला

अधिकतम ऋण 10 लाख रुपये है। 2016-17 के दौरान खोले गये कुल 34,880,924 खातों में से 6,114,737 खाते अनुसूचित जातियों द्वारा खोले गये।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 जनवरी, 2016 को नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अनावरण किया। यह योजना किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो खेती के लिए ऋण लेते हैं। यह योजना मौसम की अनिश्चितता के खिलाफ उन्हें सुरक्षोपाय प्रदान करेगा।

बीमा दावों की निपटान प्रकिया को भी त्वरित एवं सरल बनाने का निर्णय किया गया है जिससे कि किसानों को फसल बीमा योजना को लेकर किसी समस्या का सामना न करना पड़े। संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से इस योजना का कार्यान्वयन भारत के प्रत्येक राज्य में किया जाएगा। इस योजना का प्रबंधन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाएगा। इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए 1484.67 करोड़ रुपये की एक राशि निर्धारित की गयी है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

केन्द्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) का कार्यान्वयन 2500 अनुसूचित जाति बहुल गावों के समेकित विकास के लिए किया जा रहा है, जहां अनुसूचित जाति आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है। 5 राज्यों में 372 गावों को आदर्श ग्राम के रुप में घोषित किया गया है। इसका लक्ष्य अवसंरचना संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण में अंतरों को पाटना है।

अनुसूचित जाति कल्याण कार्यक्रम

भारत सरकार के 26 विभागों/मंत्रालयों में 2017-18 में अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 233 योजनाओं हेतु 52393.55 करोड़ रुपये की एक राशि आवंटित की गयी है। यह 2016-17 की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है। इन योजनाओं के तहत यह राशि इन योजनाओं के लिए आवंटित कुल बजट के लगभग 20.20 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज अर्जित करने तथा स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की। इस मिशन का लक्ष्य 2019 तक स्वच्छ भारत अर्जित करना है जो कि महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी पर उन्हें एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता मिशन का अर्थ होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तरों में बेहतरी लाना। इस कार्यक्रम का संचालन पीने का पानी एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए बनाये गये शौचालयों की कुल संख्या 76.8 लाख की रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पीने का पानी कार्यक्रम

देश में पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। भारत सरकार केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पीने का पानी मिशन के तहत वित्तीय सहायता उपलबध कराने के द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों का संपूरण करती है। इस कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति बहुल निवास स्थानों को राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में कवर किया गया है तथा पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 30414 अनुसूचित जाति के निवास स्थानों को कवर किया गया है।

शैक्षणिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी

इस योजना का कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी समाज के आर्थिक रूप से निर्बल वर्गों को प्रदान की जाती है, अर्थात ऐसे छात्रों को जिनके माता-पिता की आय 4.5 लाख रूपये वार्षिक तक है। उन्हें यह सहायता भारत में उच्चतर शिक्षा के संबंधित निकायों द्वारा समुचित रूप से मान्यता प्राप्त एवं अनुमोदित व्यावसायिक पाठयक्रमों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों को ब्याज सब्सिडी और लाभार्थियों की संख्या 1.1 लाख रही है, जो 376 करोड़ रूपये के बराबर है।

आईआईटी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उपलब्ध कराये जाने वाले लाभ

बी.टेक, डुअल डिग्री, एम.टेक, एम.एस.सी., एम.एस. एवं पीएचडी कार्यक्रमों में नामांकित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी छात्रों को टयूशन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाती है। भले ही उनके माता-पिता की आय कितनी भी क्यों न रही हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संस्थान छात्रवृत्ति धारकों को प्रति सेमेस्टर 500 रूपये के छात्रावास सीट किराये के भुगतान से भी छूट प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं, यथा–मेस की निशुल्क सुविधा (मूलभूत मेनू) और 250 रूपये प्रति महीने का जेब भत्ता प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि उनके माता पिता की आय दो लाख रुपये वार्षिक से कम हो। आईआईटी के पास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों पर ध्यान देने के लिए एक संपर्क अधिकारी/शिकायत समिति होती है। ■

कांग्रेस बनाम जनसंघ

– दीनदयाल उपाध्याय

स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद ध्येयविहीन कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं के समक्ष यह समस्या थी कि अब कौन सी वस्तु शेष है, जिसके लिए अपनी सेवाएं समर्पित की जाएं? कांग्रेस की इस ध्येयविहीनता को महात्मा गांधी ने समझा था और इसलिए वे कांग्रेस को समाप्त कर देने पर बराबर जोर देते थे, किंतु कांग्रेस के अन्य नेताओं ने कांग्रेस को अपने स्वार्थ का साधन बना लिया और उसे भंग नहीं किया।

उद्देश्य समाप्त होने पर संस्था निर्जीव हो जाती है। कांग्रेस का काम खत्म हो गया, अब उसे समाप्त कर देना चाहिए था। परंतु नेताओं ने इसे भी नहीं माना। फलतः मृत कांग्रेस के शव को पंडित नेहरू लिए घूम रहे हैं और उसे जिलाने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं। कांग्रेस का शव अधिक सड़ जाने से गल-गल कर गिरा। फलतः अनेक पार्टियों का जन्म हुआ, जिसमें पहले सोशलिस्टों का नंबर है। ये सब पार्टियों केवल विरोध के लिए बनी हैं, जिनका कोई आधार नहीं। हमें तो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए एक मौलिक आधार को लेना है। हम अनुरोध करने के लिए हैं, विरोध करने के लिए नहीं। जनसंघ केवल कांग्रेस के विरोध के लिए नहीं है। देश को सुखी तथा वैभवशाली बनाने का कार्य इसके सामने प्रमुख है।

कांग्रेस की ध्येयविहीनता ने देश में निराशा का वातावरण ला दिया। लोग अनुभव करने लगे कि उनका धर्म मिट रहा है, संस्कृति मिट रही है, जीवनोपयोगी वस्तुएं अन्न- वस्त्र अलभ्य हो रहे हैं। अतः जन-मन में निराशा का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक था। जनसंघ का उदय इस निराशावाद के वातावरण को छिन्न-भिन्न कर देश में आशा और स्फूर्ति का संचार करने के लिए हुआ है।

स्वतंत्रता की लड़ाई मे कांग्रेस केवल पेशवा थी और 35 करोड़ जनता उसके साथ उस लड़ाई में संलग्न थी। नेता होने के नाते उसे स्वतंत्रता प्राप्ति का यश प्राप्त हुआ। कांग्रेस के नेता आज यह कह रहे हैं कि स्वतंत्रता हमने दिलवाई है। उन लोगों से पूछना चाहिए कि योगी अरविंद जैसे लोग तथा जिन्होंने अंडमान में अपना जीवन व्यतीत किया और हंसते हुए स्वतंत्रता के लिए ही अपने जीवन की कुर्बानी की, क्या वे कांग्रेस के झंडे के नीचे आए थे? वासुदेव बलवंत फडके कांग्रेस से बाहर ही स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे। रासबिहारी बोस, भगतसिंह तथा वीर सावरकर क्या कांग्रेसी थे? सुभाष चंद्र बोस ने भी जो महान् कार्य किए थे, वे भी कांग्रेस से अलग होने पर ही। परंतु इस सबका श्रेय कांग्रेस अपने ऊपर ले रही है। सच्ची बात तो यह है कि भारत की 40 करोड़ जनता ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और हम सबने इस युद्ध में भाग लिया।

आज सभी प्रकार के आदर्शों से दूर होकर कांग्रेस उस समय के नेतृत्व की आड़ लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रही है। उस स्वार्थ

सिद्धि के लिए योग्यता-अयोग्यता इत्यादि का कुछ विचार नहीं रखा जा रहा है। अभी हाल में मंडी के राजा को ब्राज़ील का राजदूत इसलिए बना दिया गया, क्योंकि उन्होंने राजकुमारी अमृत कौर के विरोध से अपना नाम वापस ले लिया है। पता नहीं उनमें उस पद की कहाँ तक योग्यता है।

उसी प्रकार स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही कांग्रेस सरकार ने कंट्रोल लगा रखा है। यदि कंट्रोल जनता की भलाई के लिए हो तो ठीक भी है, किंतु यहाँ पर वह इसलिए है कि उसके कारण व्यापारी और पूंजीपति कांग्रेस के अँगूठे के नीचे रहते हैं। वोट लेने के समय लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं कि उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। उनको याद दिलाया जाता है कि उन्हें कितने परमिट दिए गए हैं। इस प्रकार जनता को दुःख देने के लिए कांग्रेस और पूंजीपति मिल जाते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कांग्रेस सरकार ने 287 मन की चीनी मनमाने दामों में मिल मालिकों को बेचने की आज्ञा इसलिए दे दी थी कि उन्होंने कांग्रेस फंड में कुछ चंदा दे दिया था। कांग्रेस ने देश में तीन भयंकर भूलें की हैं। पहली, बिना किसी आदर्श के कार्य किया है; दूसरी, केवल अपनी पार्टी की स्वार्थसिद्धि की है; तीसरी, यदि आदर्श सम्मुख रखा भी तो वह विदेशी। उदाहरणस्वरूप यदि आज हमारे देश में अन्न की कमी है तो उसके लिए हमने विदेशों से ट्रैक्टर मंगाए किंतु यहां चलेंगे कैसे? मकानों की कमी होने पर हमने सीमेंट, लोहा और ईंट जनता को देने के बजाय मकान बनाने

की फैक्टरी स्थापित की और करोड़ों रुपए फूंक दिए।

भारतीय जनसंघ का उद्देश्य भारतीय जीवन के लिए अत्यंत पवित्र और स्फूर्तिदायक है। ये सिद्धांत और आदर्श नए नहीं हैं। वे इतने पुराने हैं कि जबसे मानव मानव को पहचानने लगा, प्रकृति का प्रादुर्भाव इस भूमि पर हुआ तथा भारत भूमि को पहचानने के साथ राष्ट्रीयता का उदय हुआ। केवल एक राष्ट्रीयता की भावना को लेकर, जिसको 'एकं सद्विप्राःबहुधा वदन्ति' कहा गया है-जनसंघ खड़ा हुआ है। इसीलिए देश के कोने-कोने में जहां जनसंघ गया है, जनता में उसका आदर हुआ है।

भारतीय जनसंघ का जन्म देश के सम्मुख एक स्वदेशीय आदर्शवाद रखने के निमित्त हुआ और उसका आधार कुछ मर्यादाओं पर स्थिर है। प्रथम तो जनसंघ भौगोलिक मर्यादा को मानता है और यह कहता है कि देश का विभाजन गलत है। यह ध्यान रखना चाहिए कि यह कहना भावनाओं को उभारना नहीं है, वरन् कुछ तथ्यों को तर्क की कसौटी पर कसना है। आज हमारे देश में अन्न की कमी है और करोड़ों रुपयों का अन्न हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। पाकिस्तान में वह बहुतायत से है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पास कोयला, लोहा और कपड़ा नहीं है, जिसके लिए उसको परेशानी होती है। पूर्वी बंगाल

भारतीय जनसंघ का जन्म देश के सम्मुख एक स्वदेशीय आदर्शवाद रखने के निमित्त हुआ और उसका आधार कुछ मर्यादाओं पर स्थिर है। प्रथम तो जनसंघ भौगोलिक मर्यादा को मानता है और यह कहता है कि देश का विभाजन गलत है। यह ध्यान रखना चाहिए कि यह कहना भावनाओं को उभारना नहीं है, वरन् कुछ तथ्यों को तर्क की कसौटी पर कसना है।

में जूट सड़ रहा है, पश्चिम में जूट मिलें बंद हैं। पाकिस्तान में रुई बहुतायत है, हम उसे तेज दामों पर मिस्र या अमरीका से खरीद रहे हैं। यदि दोनों देश एक हो जाएँ तो आर्थिक दृष्टि से हम फिर स्वावलंबी बन सकते हैं और हमारी सारी समस्याएँ हल हो सकती हैं।

सुरक्षा की दृष्टि से हम अपने बजट का 55 प्रतिशत और पाकिस्तान 60 प्रतिशत केवल सेना पर व्यय कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों की आर्थिक अवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। साथ-ही-साथ इस विभाजन के ही कारण हमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहकर अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ रही है, क्योंकि दोनों को यह डर है कि एक के द्वारा उसका साथ छोड़ देने पर अंग्रेज दूसरे की अधिक सहायता करेगा।

सांप्रदायिक समस्या का भी हल इस विभाजन से नहीं हुआ, क्योंकि यदि कल 35 करोड़ में 10 करोड़ मुसलमान भारत में थे तो आज चार करोड़ रह गए हैं, किंतु वह समस्या हल नहीं हुई। दूसरी ओर पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं पर अत्याचार और उनका निष्कासन हमारी आर्थिक तथा राजनीतिक दशा को हर समय चिंतायुक्त बनाए रखते हैं।

कश्मीर समस्या का भी सबसे सरल हल विभाजन का अंत है। इस प्रकार सब दृष्टियों से अखंडता अनिवार्य है। किंतु लोग कहते हैं कि यह बेमानी है। उत्तरी तथा दक्षिण कोरिया, मिस्र तथा सूडान और आयरलैंड इत्यादि की एकता की बात तथा उसका समर्थन करने वाले लोग भारत तथा पाकिस्तान की एकता को सुनकर केवल इसलिए बौखला जाते हैं कि उससे उनके स्वार्थों का हनन होता है। आठ साल पूर्व पाकिस्तान का बनना बेहूदा बात थी, किंतु वह बन गया। आज अखंडता 'बेहूदा' है, कल उन्हीं लोगों के सम्मुख वह भी हो जाएगा।

अखंड भारत की मांग हमारी नैतिक मांग है, क्योंकि श्री जिन्ना के अदला-बदली के प्रस्ताव को न मानकर अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की शर्त हिंदुस्थान और पाकिस्तान दोनों के लिए कांग्रेस ने रखी थी। उस समय महात्माजी ने कहा था कि इस शर्त के पूरे न होने पर इनमें से कोई भी देश की अखंडता की मांग कर सकता है। हमने अपनी शर्त पूरी कर दी है और अपना अधिकार प्राप्त कर लिया है। चार करोड़ मुसलमानों की रक्षा करने के लिए हिंदुस्थान का प्रत्येक दल तैयार है परंतु पाकिस्तान ने इस शर्त को पूरा नहीं किया। पूर्वी बंगाल के हिंदुओं पर किया गया बर्बर अत्याचार ही प्रमाण के लिए पर्याप्त है। पंडित नेहरू इसके लिए आज क्या कर रहे हैं? सरदार पटेल तो सांप्रदायिक नहीं थे, उन्होंने भी कहा था निर्वासितों को रखने के लिए आधा बंगाल पाकिस्तान से मांगा जाएगा। आज इस प्रश्न को नेहरूजी क्यों नहीं रखते?

किंतु यह अखंडता किसी आक्रमण से नहीं प्राप्त होगी। यह समस्या का ठीक हल नहीं है। वह तभी होगा जब यहां का हिंदू और यहाँ का मुसलमान इन बातों को समझ लेगा कि उसका भला इसी में है और यह विचार दिनोदिन जोर पकड़ते-पकड़ते एक दिन यह संभव हो जाएगा। विचारों के ही कारण भारत बँटा है, विचारों से ही यह एक होगा।

हमारी दूसरी मर्यादा एक राष्ट्र में विश्वास है। हम मुस्लिम लीग के द्वि-राष्ट्रवाद को नहीं मानते। हमारा कहना यह है कि यदि फारस, चीन और तुर्की का मुसलमान अपने धर्म को मानता हुआ अलग-अलग राष्ट्रीयता मानता है तो भारत का मुसलमान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? उन देशों में लोग अपने देश की भाषा और संस्कृति को मानते हैं। यहाँ भी मुसलमानों को इस देश की संस्कृति और राष्ट्रभाषा हिंदी को मानना चाहिए। *(क्रमशः)* ■

साभार : पांचजन्य, जनवरी ३, १९५२

गुरूदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर

(7 मई 1861 - 7 अगस्त 1941)

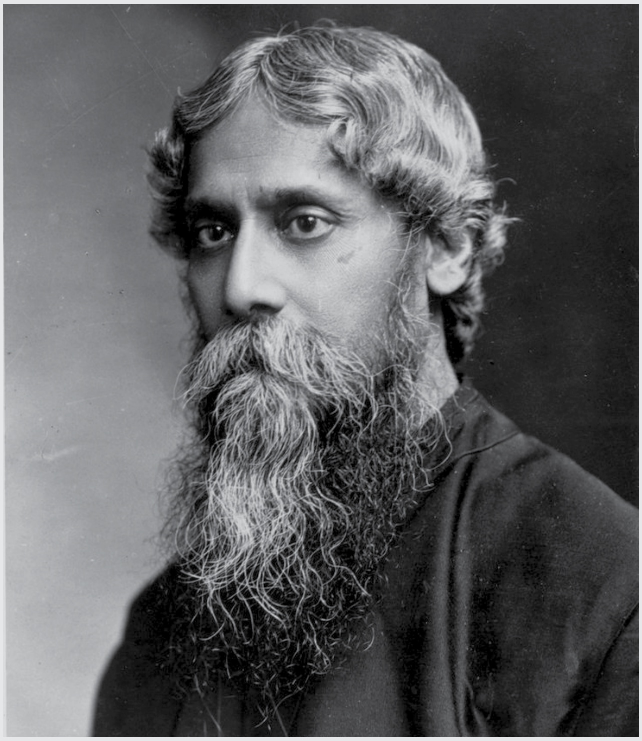

भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ रूप से पश्चिमी देशों का परिचय और पश्चिमी देशों की संस्कृति से भारत का परिचय कराने में गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की बड़ी भूमिका रही है। इन्हें आधुनिक भारत का असाधरण सृजनशील कलाकार माना जाता है। रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई, 1861 को कलकत्ता के प्रसिद्ध जोर सांको भवन में हुआ था। आपके पिता देवेन्द्रनाथ टैगोर (देवेन्द्रनाथ ठाकुर) ब्रह्म समाज के नेता थे। आप उनके सबसे छोटे पुत्र थे। आपका परिवार कोलकत्ता के प्रसिद्ध व समृद्ध परिवारों में से एक था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री टैगोर सहज ही कला के कई स्वरूपों की ओर आकृष्ट हुए जैसे- साहित्य, कविता, नृत्य और संगीत।

रवीन्द्रनाथ टैगोर की स्कूल की पढ़ाई प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। टैगोर ने बैरिस्टर बनने की चाहत में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटोन पब्लिक स्कूल में नाम दर्ज कराया। उन्होंने लंदन कॉलिज विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1880 में बिना डिग्री हासिल किए ही वापस आ गए। रवीन्द्रनाथ टैगोर को बचपन से ही कविताएं और कहानियां लिखने का शौक था। उनके पिता देवेन्द्रनाथ ठाकुर एक रवीन्द्र का मन साहित्य में ही रमता था। उन्हें अपने मन के भावों को कागज पर उतारना पसंद था। आखिरकार, उनके पिता ने पढ़ाई के बीच में ही उन्हें वापस भारत बुला लिया और उन पर घर-परिवार की जिम्मेदारियां डाल दीं। रवीन्द्रनाथ टैगोर को प्रकृति से बहुत प्यार था। वे गुरुदेव के नाम से लोकप्रिय थे।

भारत आकर गुरुदेव ने फिर से लिखने का काम शुरूकिया। 16 अक्तूबर 1905 को रवीन्द्रनाथ के नेतृत्व में कोलकाता में मनाया गया रक्षाबंधन उत्सव से 'बंग-भंग आंदोलन' का आरम्भ हुआ। इसी आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया। टैगोर ने विश्व के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक जलियांवाला कांड (1919) की घोर निंदा की और इसके विरोध में उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन द्वारा प्रदान की गई, 'नाइट हुड' की उपाधि लौटा दी।

भारत आकर गुरुदेव ने फिर से लिखने का काम शुरू किया। 16 अक्तूबर 1905 को रवीन्द्रनाथ के नेतृत्व में कोलकाता में मनाया गया रक्षाबंधन उत्सव से 'बंग-भंग आंदोलन' का आरम्भ हुआ। इसी आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया। टैगोर ने विश्व के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक जलियांवाला कांड (1919) की घोर निंदा की और इसके विरोध में उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन द्वारा प्रदान की गई, 'नाइट हुड' की उपाधि लौटा दी। 'नाइट हुड' मिलने पर नाम के साथ 'सर' लगाया जाता है। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनीं। भारत का राष्ट्र-गान 'जन गण, मन अधिनायक जय है...' और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान 'आमार सोनार बांग्ला...' गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। 7 अगस्त, 1941 को कलकत्ता में इस बहुमुखी साहित्यकार का निधन हो गया। ■

भारत-बांग्लादेश के बीच 22 समझौतों पर हस्ताक्षर

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना 7 अप्रैल को 4 दिवसीय दौरे पर भारत आईं। गौरतलब है कि श्री मोदी खुद श्रीमती हसीना को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। श्रीमती शेख हसीना के इस यात्रा के दौरान भारत-बांग्लादेश के बीच 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने बांग्लादेश को 4.5 अरब डॉलर के कर्ज की घोषणा की। उन्होंने बांग्लादेश को सैन्य आपूर्ति के लिए अतिरिक्त 50 करोड़ डॉलर के कर्ज की भी घोषणा की। इस 4.5 अरब डॉलर के कर्ज से बांग्लादेश में परियोजना में काम किया जाएगा। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में भारत की ओर से बांग्लादेश को मिलने वाला कर्ज कुल आठ अरब डॉलर पहुंच गया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत लगातार बांग्लादेश के साथ सहयोग करता रहेगा। साथ ही श्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें अपने कारोबार में विविधता लाने की जरूरत है। श्रीमती शेख हसीना ने कहा कि हम दोनों देश की सीमा को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। उन्होंने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेकने की भी बात कही।

कोलकाता- खुलना-ढाका बस सेवा की कोलकाता से शुरुआत

8 अप्रैल को कोलकाता से **कोलकाता- खुलना- ढाका** बस सेवा की औपचारिक शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनकी बांग्लादेश समकक्ष श्रीमती शेख हसीना एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में संयुक्त रूप से समारोह की शुरुआत की। यह द्विपक्षीय सम्बन्धों को सुदृढ़ करने एवं दोनों देशों के नागरिकों को बेहतर सड़क एवं रेल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए की जा रही अनेक शुरुआतों का भाग है।

नई नवेली **कोलकाता- खुलना- ढाका** बस सेवा के अतिरिक्त **कोलकाता- ढाका** और **कोलकाता- ढाका- आगरतला** मार्गों पर भी बस सेवाएं प्रचालित की जा रही हैं। उनका संचालन पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा के राज्य परिवहन निगमों और बांग्लादेश परिवहन निगम की ओर से किया जा रहा है। अब कोलकाता और खुलना पहली बार बस-रूट से सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। कोलकाता से खुलना होते हुए ढाका के 409 किलोमीटर लंबे रास्ते में दोनों ओर से सप्ताह के तीन दिन दो बसें चलेंगी।

बांग्लादेश का जन्म एक नयी आशा का उदयः नरेंद्र मोदी

बांग्लादेश लिबरेशन वार में शहीद हुए भारतीयों का सम्मान करने के लिए आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल को कहा कि आज एक विशेष दिन है। आज भारत तथा बांग्लादेश के शहीदों के बलिदान को स्मरण करने का दिन है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए जिंदगी देने वाले योद्धाओं को याद करने का दिन है। बांग्लादेश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ने वाले भारतीय फौज के जांबाजों को याद करने का दिन है, लेकिन ये अवसर बांग्लादेश पर किए गए उस क्रूर प्रहार को भी याद करने का है जिसने लाखों इंसानों की जिंदगी छीन ली। किन्तु साथ ही साथ इतिहास की जो त्रासदी बांग्लादेश पर गुज़री, उसके पीछे की विकराल मानसिकता को नकारने का भी है।

उन्होंने कहा कि आज का ये अवसर भारत और बांग्लादेश के 140 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के बीच अटूट विश्वास की ताकत को पहचानने का है। हम अपने समाजों को कैसा एक सशक्त तथा समृद्ध भविष्य दें इस पर चिंतन करने का भी यह उचित अवसर है।

श्री मोदी ने कहा कि कई कारणों से आज का दिन ऐतिहासिक है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए सभी भारतीय सैनिकों के परिवारों के लिए भी ये कभी न भूल पाने वाला क्षण है। आज बांग्लादेश उन 1661 भारतीय सैनिकों का सम्मान कर रहा है, जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की क़ुरबानी दी थी। मैं भारत के सवा सौ करोड़ लोगों की तरफ से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का; वहां की सरकार और बांग्लादेश के लोगों का; इस भावनात्मक पहल के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के वीर सैनिक तथा हमारी गौरवशाली सेना केवल बांग्लादेश के साथ हो रहे अन्याय एवं नरसंहार के खिलाफ नहीं लड़े थे। यह वीर, भारतीय संस्कृति में निहित मानव मूल्यों के लिए भी लड़े थे। यह मेरा परम सौभाग्य है कि इस समय 7 भारतीय शहीदों के परिवार यहां उपस्थित हैं। पूरा भारत आपकी व्यथा, आपका दर्द और आपकी पीड़ा में सहभागी है। आपका त्याग और तपस्या अतुलनीय है। भारतीय सैनिकों के बलिदानों के लिए मैं और पूरा देश सभी शहीदों को कोटि-कोटि नमन करते हैं। ■

वरिष्ठ नागरिकों के लिए "राष्ट्रीय वयोश्री योजना" का शुभारम्भ

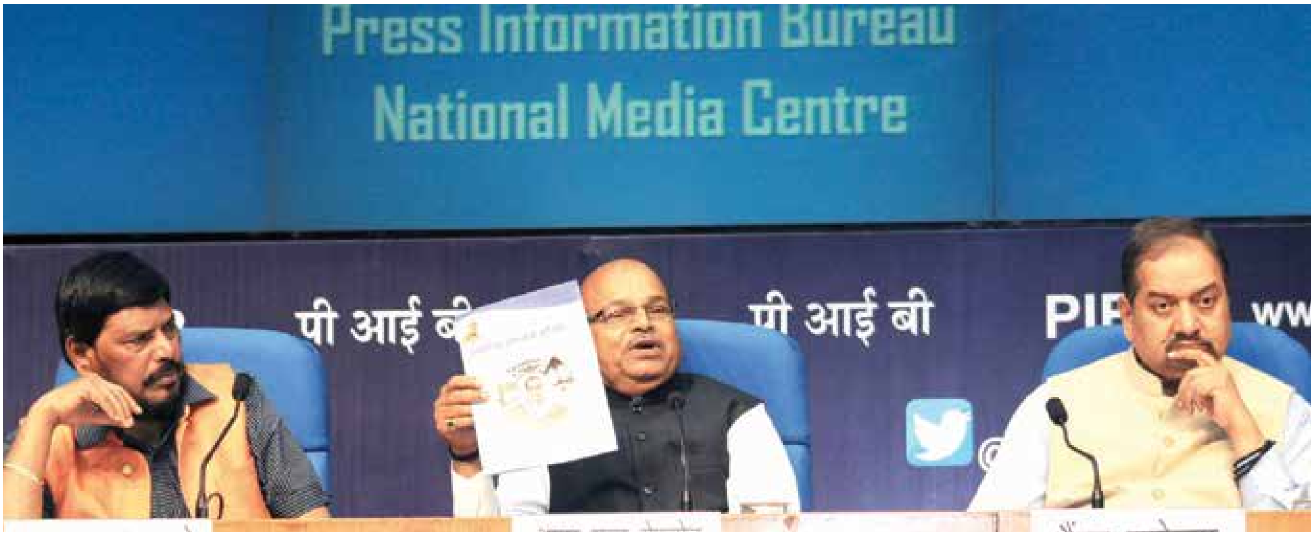

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव)/विमुक्त, घुमंतु और अर्द्ध-घुमंतु जातियों के विद्यार्थियों के लिए 14 स्कालरशिप योजनाएं डिजिटल भुगतान के अंतर्गत संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ 3.54 करोड़ विद्यार्थियों को मिल रहा है।

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। इस दिशा में एकात्मकता, समता और सामाजिक समरसता दिशा-निर्देशक सिद्धांत हैं। यह बात 15-अप्रैल को डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के सिलसिले में "प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों" के बारे में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने कही। सामाजिक न्याय और अधिकारिता न्याय मंत्री श्री रामदास अठावले भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

श्री गहलोत ने पत्रकारों को बताया कि अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव)/विमुक्त, घुमंतु और अर्द्ध-घुमंतु जातियों के विद्यार्थियों के लिए 14 स्कालरशिप योजनाएं डिजिटल भुगतान के अंतर्गत संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ 3.54 करोड़ विद्यार्थियों को मिल रहा है। छात्रवृत्ति की समस्त राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है और अजा विद्यार्थियों के 60 प्रतिशत बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्तियों, विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों, प्रशिक्षण सुविधाओं, परिसरों, संस्थानों के निर्माण/उन्नयन के लिए पूंजी प्रदान करने आदि उपायों के जरिए अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध विद्यार्थियों का शैक्षिक सशक्तिकरण किया जा रहा है।

भारत सरकार का यह विश्वास है कि सब के लिए शिक्षा सशक्तिकरण की कुंजी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अलग अलग तरह की सात छात्रवृत्तियां कार्यान्वित करता है, जिनमें मैट्रिक-परवर्ती और मैट्रिक-पूर्ववर्ती छात्रवृत्तियां, टॉप क्लास स्कालरशिप, राष्ट्रीय विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, अनुसूचित जातियों के लिए यूजीसी द्वारा संचालित राष्ट्रीय फेलोशिप, अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक स्कालरशिप, अनुसूचित जातियों और अपिव के लिए निशुल्क कोचिंग (70:30 अनुपात में) और योग्यता उन्नयन छात्रवृत्तियां शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपने बजट का करीब 54 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्तियों पर खर्च करता है।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए अनुसूचित जातियों की प्रगति और उन्हें लक्षित लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

(अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम, 1989, में संशोधन किया गया और संशोधित अधिनियम 26.01.2016 से लागू किया गया। अब यह अधिदेशित किया गया है कि अजा/अजजा के प्रति अत्याचारों से संबंधित मामलों की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से दो महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

अधिनियम के अंतर्गत संशोधित नियम, 2016, पिछले वर्ष 14 अप्रैल से प्रवृत्त हो गए हैं। नए अपराधों और प्रचलित अपराधों के मामले में पीड़ितों के लिए राहत में वृद्धि की गई है। पहली बार इन अपराधों में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार को शामिल किया गया है। सामूहिक बलात्कार के मामले में राहत राशि बढ़ा कर 8.25 लाख रुपये कर दी गई है और बलात्कार के मामले में राहत राशि पूर्ववर्ती 1.20 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। विशेष अदालतों की संख्या 194 पर पहुंच गई है। 32 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जिला सत्र अदालतों को विशेष अदालत निर्दिष्ट किया गया है। 5 राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति किए गए अपराधों की शिकायतों के पंजीकरण के लिए विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

अनुसूचित जातियों के कौशल विकास और उद्यमिता के संदर्भ में श्री गहलोत ने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए 2014-15 में उद्यम पूंजी निधि कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसकी विशिष्टता यह है कि इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के उद्यमियों को 50 लाख रुपये से लेकर 15 करोड़ रुपये तक के उच्चतर ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक 65 अनुसूचित जाति उद्यमियों को 236.66 करोड़ रुपये की ऋण राशि मंजूर की जा चुकी है, जो सौर ऊर्जा, जल शोधन संयंत्रों, खाद्य प्रसंस्करण और पेय पदार्थों, होटल आदि से सम्बद्ध हैं। उन्होंने बताया कि 9 परियोजनाओं में लाभार्थियों ने ऋणों की अदायगी प्रारंभ कर दी है और अन्य अजा उद्यमियों को भी इस स्कीम का कई गुना लाभ हुआ है।

जहां तक कौशल विकास का सवाल है, सभी राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है और 2014-15 से 2016-17 की अवधि में करीब 1.5 लाख लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत 48.42 प्रतिशत लोगों को दिहाड़ी/स्व-रोजगार प्राप्त हुआ।

श्री गहलोत ने कहा कि उद्यमशीलता के तहत अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में आर्थिक गतिविधियों हेतु लिए गए ऋण पर दी गई सब्सिडी से 17 लाख से भी ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। पिछले तीन वर्षो के दौरान उद्यमशीलता के लिए निगमों द्वारा 12 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों को ऋण दिए गए हैं।

उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को उपादान व जीवन के लिए उपयोगी उपकरणों के वितरण हेतु एक नई योजना 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना' आरंभ की गई है जो कि उनकी उम्र से संबंधित शारीरिक क्षति को दूर करने तथा उन्हें देखभाल करने वालों या परिवार के अन्य सदस्यों पर कम से कम निर्भरता के साथ एक सम्मानजनक और उत्पादक जीवन जीने में मदद करेगी। देश में अपनी तरह की इस पहली महत्वाकांक्षी योजना के तीन वर्षों की अवधि में 5 लाख 20 हजार वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है।

मंत्री महोदय ने कहा कि अनुसूचित जाति उपयोजना स्कीम को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत गरीबी रेखा से नीचे की अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए राज्यों को शत प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। आर्थिक कार्यकलाप हेतु लिए गए ऋण पर अधिकतम 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति की सब्सिडी प्रदान करने के लिए सहायता का उपयोग किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान सब्सिडी घटक से लगभग 17 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या बहुल गांवों में बुनियादी ढांचों (सौर ऊर्जा, पीने का पानी, सड़क आदि) की सुविधा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों के कौशल विकास के लिए निधियां जारी की जाती है।

अनुसूचित जातियों के लिए 2014-15 में उद्यम पूंजी निधि कार्यक्रम शुरूकिया गया था। इसकी विशिष्टता यह है कि इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के उद्यमियों को 50 लाख रुपये से लेकर 15 करोड़ रुपये तक के उच्चतर ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक 65 अनुसूचित जाति उद्यमियों को 236.66 करोड़ रुपये की ऋण राशि मंजूर की जा चुकी है, जो सौर ऊर्जा, जल शोधन संयंत्रों, खाद्य प्रसंस्करण और पेय पदार्थों, होटल आदि से सम्बद्ध हैं।

उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर की स्मृति में उनके मंत्रालय ने 2014-15 में निम्नलिखित तीन योजनाएं आरंभ कीं: (1) खानाबदोश समुदाय के छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में सुविधा प्रदान करने के लिए विमुक्त, खानाबदोश एवं अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों (डीएनटी) के लिए पूर्व एवं छात्रवृत्ति योजना, (2) आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के छात्रों को उच्चतर शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में

सहायता प्रदान करने हेतु डॉ. अम्बेडकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्ति योजना एवं (3) अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए विदेशों में पढ़ाई करने के लिए डॉ. अम्बेडकर ब्याज सब्सिडी योजना। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद ओबीसी एवं ईबीसी छात्रों को विदेशों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता करना है।

श्री गहलोत ने आगे कहा कि डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा सहायता गंभीर बीमारी से पीड़ित उन मरीजों को प्रदान की जाती है जिन्हें किडनी, हृदय, यकृत, कैंसर और मस्तिष्क अथवा अन्य जीवनघातक बीमारियों के संबंध में सर्जरी की आवश्यकता होती है, जिनमें आर्गन ट्रांसप्लांट तथा स्पाइनल सर्जरी भी शामिल है और यह इलाज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय प्रति वर्ष 2,50,000/-रुपये से कम है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 168 मरीजों को सहायता प्रदान की गई है।

मंत्री महोदय ने अंतरजातीय विवाहों के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य, नवविवाहित दम्पत्तियों द्वारा अंतरजातीय विवाह करने का साहसिक कदम उठाने की प्रशंसा करना तथा इस दम्पत्ति को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि वे अपने विवाहित जीवन की शुरुआत आसानी से कर सकें। प्रत्येक दम्पत्ति को 5 लाख रुपये की धनराशि दो किस्तों में जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 121 दंपत्तियों को सहायता प्रदान की गई है।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि महान संतों की जयंती/पुण्य तिथि मनाने के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना के तहत मान्यता प्राप्त कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानोंऔर पंजीकृत एनजीओ, जो कम से कम दो वर्षों से अस्तित्व में हैं, को उन महान संतों की जयंती मनाने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने केलिए तैयार किया गया है, जिन्होंने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, असमानता और भेदभाव को मिटाने तथा समाज के दुर्बल वर्गों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। पिछले दो वर्षो के दौरान, 43 एनजीओ को अनुदान जारी किया गया है।

उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर से संबंधित निम्नलिखित स्थानों जैसे जन्मभूमिः महू, शिक्षा भूमिः 10 किंग हेनरी रोड लंदन, दीक्षा भूमिःनागपुर, परिनिर्वाण भूमिः 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली और चैत्य भूमिः दादर मुंबई को भारत सरकार द्वारा 'पंचतीर्थ' घोषित किया गया है।

मंत्री महोदय ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन ने डॉ. अम्बेडकर से जुड़े प्रमुख स्थानों के विकास के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया। महद में मेमोरियल के विकास के लिए 13,36,000,00/- रुपये की राशि मंजूरी दी गई है। महाड सत्याग्रह का नेतृत्व 20 मार्च 1927 को डॉ. बी.ए.आर अम्बेडकर ने किया था, ताकि सार्वजनिक टैंक से पानी का उपयोग करने के लिए दलित लोगों को अनुमति दी जा सके। महाराष्ट्र के चिंचोली में संग्रहालय भवन के लिए डीएम नागपुर को 4,36,90,685 रुपये की राशि जारी की गई है।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति उपयोजना/जनजातीय उपयोजना राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार द्वारा भावना में लागू की गई है। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए आवंटन को 2016-17 के बजट अनुमान के 38,833 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2017-18 में 52,393 करोड़ रुपये कर दिया गया है जो लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। अब अनुसूचित जाति उपयोजना की निगरानी और कार्यान्वयन का दायित्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

श्री गहलोत ने कहा कि उनका मंत्रालय मैला ढोने वालों को इस अमानवीय प्रचलन से मुक्त करने के लिए उन्हें 40 हजार रुपये की एक मुश्त सहायता प्रदान करता है और उन्हें मेहतर पुनर्वास योजना

इस योजना का उद्देश्य, नवविवाहित दम्पत्तियों द्वारा अंतरजातीय विवाह करने का साहसिक कदम उठाने की प्रशंसा करना तथा इस दम्पत्ति को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है ताकि वे अपने विवाहित जीवन की शुरुआत आसानी से कर सकें। प्रत्येक दम्पत्ति को 5 लाख रुपये की धनराशि दो किस्तों में जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 121 दंपत्तियों को सहायता प्रदान की गई है।

के तहत वैकल्पिक रोजगार की सुविधा प्रदान करने के लिए कौशल प्रशिक्षण एवं निम्न दरों पर ऋण भी उपलब्ध कराता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 11598 लोगों को एक मुश्त सहायता प्रदान की गई है तथा 13,827 लोगों ने कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू किया है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रत्येक शाखा को वित्त मंत्रालय द्वारा एक उद्यमी के रूप में कम से कम एक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के युवक की सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे कि उनके बीच अधिक रोजगार का सृजन किया जा सके। ■

संसद के दोनों सदनों ने 18 विधेयक को दी मंजूरी

'वस्तु और सेवा कर' अधिनियम सर्वसम्मति से पारित

संसद का बजट सत्र 2017 अनेक दृष्टि से ऐतिहासिक रहा। यह सत्र 31 जनवरी, 2017 को आरंभ हुआ तथा इसे 12 अप्रैल, 2017 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र कई मामलों में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि वाला रहा। जैसे-केंद्रीय बजट का पहले प्रस्तुतीकरण और 31 मार्च तक नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले सरकार के सभी वित्तीय कामकाज पूरे किए गए। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के सभी सहायक अधिनियमों को पारित करना। एकीकृत बजट प्रस्तुत और पारित करना। दरअसल, ऐसा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली के विजनरी नेतृत्व और संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों की भागीदारी से संभव हो सका। सार्वजनिक महत्व के विभिन्न विषयों पर सार्थक बहस हुई।

गौरतलब है कि भारत के विधायी इतिहास में पहली बार 31 मार्च तक अगला वित्त वर्ष प्रारंभ होने से पहले सरकार के सभी वित्तीय काम-काज पूरे कर लिये गए। यह काम अल्प अवधि में नहीं किया गया, बल्कि सामान्य चर्चा की गई। स्थायी समितियों ने विचार किया और कुछ मंत्रालयों पर चर्चा भी हुई। अतीत में वित्तीय कामकाज 31 मार्च के पहले पूरे किये जाते थे और उन वर्षों में या तो चुनाव होना होता था और अंतरिम बजट पेश किया जाता था या संसदीय समितियां अन्य मामलों की जांच करती थीं। यह एक बहुत बड़ा वित्तीय सुधार है और इससे विकास परियोजनाओं को चालू करने के लिए मंत्रालयों को पूरा धन उपलब्ध हुआ है। यह पहला मौका है जब बजट सत्र के दौरान लेखानुदान पारित किया गया।

बजट सत्र के पहले भाग में लोक सभा के 7 और राज्य सभा की 8 बैठकें हुई। सत्र के दूसरे हिस्से में लोक सभा की 22 और राज्य सभा की 21 बैठकें हुईं। पूरे सत्र के दौरान लोक सभा और राज्य सभा की 29-29 बैठकें हुई। लोकसभा में 113.27 प्रतिशत और राज्य सभा में 92.43 प्रतिशत कार्य हुए। बाधा के कारण लोकसभा में 8 घंटे और राज्य सभा में 18 घंटे का नुकसान हुआ और इसकी भरपाई लोक सभा की 19 घंटे की बैठक और राज्य सभा की 7 घंटों की अधिक बैठक से की गई।

वर्ष का पहला सत्र होने के कारण राष्ट्रपति ने 31 जनवरी, को संविधान के अनुच्छेद 87 (1) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और संसद सत्र आहुत करने के बारे में बताया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया और इस चर्चा हुई। सत्र के पहले हिस्से में धन्यवाद प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। 9 फरवरी, 2017 को दोनों सदनों की बैठक छुट्टी के लिए 27 दिनों के लिए स्थगित की गई और दोनों सदनों की बैठक फिर 9 मार्च, 2017 को हुई, ताकि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर संबंधित स्थायी समितियां विचार कर सकें।

सत्र के पहले भाग में 1 फरवरी, 2017 को केंद्रीय बजट 2017-18 प्रस्तुत किया गया। इस बार आम बजट में रेल बजट को मिलाकर बजट प्रस्तुत हुआ। दोनों सदनों में बजट पर सामान्य

भारत के विधायी इतिहास में पहली बार 31 मार्च तक अगला वित्त वर्ष प्रारंभ होने से पहले सरकार के सभी वित्तीय काम-काज पूरे कर लिये गए। यह काम अल्प अवधि में नहीं किया गया, बल्कि सामान्य चर्चा की गई। स्थायी समितियों ने विचार किया और कुछ मंत्रालयों पर चर्चा भी हुई। अतीत में वित्तीय कामकाज 31 मार्च के पहले पूरे किये जाते थे और उन वर्षों में या तो चुनाव होना होता था और अंतरिम बजट पेश किया जाता था या संसदीय समितियां अन्य मामलों की जांच करती थीं। यह एक बहुत बड़ा वित्तीय सुधार है

चर्चा हुई। संसद सत्र के दूसरे भाग में संबंधित स्थायी समितियों की जांच और प्रस्तुतीकरण के बाद रेलवे, गृह, रक्षा तथा कृषि मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और इन्हें बारी-बारी के लोक सभा में पारित किया गया। शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं हो पायी थी और उन्हें पारित करने के लिए सदन में रखा गया और मांगें 20 मार्च, 2017 को पास की गईं। संबंधित विनियोग विधेयक भी प्रस्तुत किया गया। इस पर विचार हुआ और पारित किया गया और बाद में इसे राज्य सभा ने वापस कर किया।

अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक भी उसी दिन पेश किया गया, उस पर विचार किया गया और फिर पारित किया गया तथा इसके बाद राज्य सभा द्वारा वापस कर दिया गया। वित्त विधेयक, 2017 लोक सभा में 22 मार्च, 2017 को पारित हुआ और राज्य सभा ने 29 मार्च, 2017 को सिफारिशों के साथ इसे वापस कर दिया। लोक सभा ने 30 मार्च, 2017 को विधेयक में राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिशों को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति ने 31 मार्च, 2017 को वित्त विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी।

वर्ष 2016-17 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों और रेलवे से संबंधित वर्ष 2013-14 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर भी लोक सभा में संबंधित विनियोग विधेयकों के साथ मतदान हुआ, जिन्हें बाद में राज्य सभा द्वारा वापस कर दिया गया। इस अवधि के दौरान केन्द्रीय बजट पर आम परिचर्चा पूरी हुई और इसके साथ ही राज्य सभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चाएं हुईं।

इस सत्र के दौरान अन्य बातों के अलावा एक खास बात यह रहीं कि चार ऐतिहासिक विधेयकों यथा- केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017, वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक 2017 और केन्द्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 को दोनों ही सदनों ने पारित कर दिया, जिससे देश भर में 01 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

इस सत्र के दौरान कुल मिलाकर 24 विधेयक (लोकसभा में 24) पेश किये गये। लोकसभा में 23 विधेयक पारित हुए और राज्य सभा में 14 विधेयक पारित हुए। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में कुल मिलाकर 18 विधेयक पारित हुए। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों जैसे कि पारिश्रमिक का भुगतान (संशोधन) विधेयक 2017, मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक 2017, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक 2017 और कर्मचारी क्षतिपूर्ति (संशोधन) विधेयक 2017 को भी इस सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया। शत्रु सम्पत्ति (संशोधन एवं वैधता) विधेयक 2017 को भी संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया।

लोक सभा में नियम 193 के तहत सतत विकास के लक्ष्यों पर अल्पकालिक चर्चा हुई, जो अपूर्ण रही। राज्य सभा में नियम 176 के तहत इन दो विषयों पर अल्पकालिक चर्चा हुईः 1. चुनाव सुधार 2. आधार – इसका क्रियान्वयन एवं इसके निहितार्थ। राज्य सभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया गया, जो विशेष श्रेणी के दर्जे की अवधारणा जारी रखने की जरूरत पर विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक आयोजित करने की आवश्यकता से संबंधित था। ■

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): आवास से घर तक

2016-17 में 32.14 लाख मकानों का निर्माण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) की शुरूआत की थी। नया ग्रामीण आवासीय कार्यक्रम घरों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से बनाया गया है। घरों में रसोईघर, शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और जलापूर्ति की सुविधा होगी तथा लाभार्थी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार घरों की योजना बना सकेंगे।

ग्रामीण राजगीरों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, ताकि बेहतर निर्माण के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध हो सके। लाभार्थियों के चयन के लिए कठोर प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आंकड़े बे-घरबार लोगों या कच्ची छत वाले 0, 1, 2 कच्चे कमरों पर आधारित हैं। एसईसीसी आंकड़ों को ग्राम सभा द्वारा मान्यता प्राप्त है, ताकि किसी प्रकार की गलती न हो। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016-17 के लिए कुल 44 लाख मकानों को स्वीकृति दी गई है तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय पूरा प्रयास कर रहा है कि इन्हें दिसंबर, 2017 तक पूरा कर लिया जाए। पीएमएवाई-जी में 6 से 12 महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्यों से मिली रिपोर्टों के अनुसार 2016-17 में कुल 32.14 लाख मकानों का निर्माण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और असम ने पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई है। बिहार, पश्चिम बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अधूरे मकानों को बड़े पैमाने पर पूरा कर लिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की योजना है कि 2017-18 में 51 लाख मकानों को पूरा कर लिया जाए। अतिरिक्त 33 लाख मकानों को 2017-18 के लिए जल्द मंजूरी दे दी जाएगी। इसी संख्या में वर्ष 2018-19 में मकानों को पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है। इस तरह 2016-19 की अवधि के दौरान 1.35 करोड़ मकानों को पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह 2022 तक सब के लिए आवास का मार्ग प्रशस्त होगा।

यह विजय यात्रा मोदीजी द्वारा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का प्रतिफल है

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव में राजग को मिले ऐतिहासिक जनादेश के लिए बधाई देता है। यह विजय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार की गरीबों को समर्पित नीतियों एवं लोक कल्याण की योजनाओं को मिला जनादेश है। इस जनादेश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आजादी के बाद के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आम जन के मानस पटल पर स्थापित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सबका साथ-सबका विकास' का संकल्प लेकर आम जन जीवन के हितों में जो तमाम योजनाएं शुरू की गयीं और उन योजनाओं के माध्यम से बदलाव को जमीन पर उतारा गया, यह विजय यात्रा उन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का प्रतिफल है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनके तीन वर्ष के सुशासन और विकास को समर्पित कार्यकाल के लिए बधाई देता है। आज दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार सबका साथ और सबका विकास के लक्ष्यों को सुनिश्चित करते हुए लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं को समृद्धि और विकास के माध्यम से जमीन पर उतारने का काम सफलतापूर्वक कर रही है। समाज के सभी वर्गों की व्यापक सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए आर्थिक न्याय को स्थापित करने की वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ राजग सरकार आगे बढ़ रही है। देश और समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों में हमारे गठबंधन का आधार दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केंद्र सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, मजबूत इच्छाशक्ति से लिए गए निर्णयों एवं परिवर्तनकारी नीतियों की सराहना करता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से सरकार द्वारा किए गए प्रयास बेहद महत्वपूर्ण हैं। युवाओं के कौशल विकास, औद्योगिक श्रम क्षेत्र में जुड़े श्रमिकों के कल्याण, कृषि आय और उत्पादकता में विकास, समाज के गरीब और हाशिए के लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मुख्यधारा के अर्थतंत्र में लाने की दिशा में मिली अभूतपूर्व सफलता, सरकार की लोक कल्याण को समर्पित कार्यशैली को प्रदर्शित करता है। आधारभूत संरचना के विकास की दिशा में सांसद आदर्श ग्राम योजना, स्मार्ट सिटी योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण, डिजिटल कनेक्टीविटी के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में इस सरकार द्वारा किए गए कार्य सराहनीय हैं।

10 अप्रैल, 2017 को प्रवासी भारतीय केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में पारित प्रस्ताव

राजग सरकार ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फसल बीमा योजना के माध्यम से सूखा अथवा भारी बारिश में होने वाले नुकसान को सुरक्षा कवच प्रदान किया है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधारों को ध्यान में रखते हुए किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से ठोस पहल की है। ग्रामीण क्षेत्रों भूमिहीन वर्ग के लिए रोजगार सृजन की दिशा में भी सरकार द्वारा उठाए गए कदम प्रशंसनीय हैं।

देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामजिक सुरक्षा से वंचित था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा, जीवन सुरक्षा बीमा, पेंशन योजनाओं के माध्यम से उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा देने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से सरकार समाज के अंतिम छोर के गरीब से गरीब व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम कर रही है। राजग सरकार का प्रथम तीन वर्ष पूरी तरह से गरीबी उन्मूलन, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण एवं आर्थिक विकास की आधारशिला रखने के प्रति समर्पित रहा है। सबका साथ और सबका विकास ही हमारी मूल वैचारिक निष्ठा में अंतर्निहित है। लोक कल्याण के प्रति समर्पण की सोच और विकास परक दृष्टि ही राजग सरकार के सुशासन प्रणाली की मूल पहचान है।

कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने हमें एक भ्रष्टाचारयुक्त लचर व्यवस्था दी थी। राजग सरकार ने विकास की अवधारणा और इसके प्रति आम लोगों के नजरिए को बदल दिया है। राजग सरकार इस बात को समझ चुकी है कि आम मानव के सामजिक एवं आर्थिक विकास

को सुनिश्चित करना ही प्राथमिकता है। हमारे विकास नीति की समग्र दृष्टि समाज के प्रत्येक वर्ग के समावेशी विकास में अंतर्निहित है।

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन केंद्र सरकार की विदेश नीति एवं कूटनीतिक पहलों की सराहना की करता है जिनकी बदौलत भारत की साख वैश्विक पटल पर मजबूत हुई है। दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के मामले में सरकार का पिछला तीन वर्ष बेहद महत्वपूर्ण रहा है। राष्ट्र सुरक्षा की दृष्टि से सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मजबूत इच्छशक्ति वाला निर्णय भारत में चल रही सरकार के निर्णयकारी छवि को दिखाता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के असाधारण नेतृत्व में भारत एक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के तौर पर दुनिया में अपनी पहचान कायम करने में सफल हुआ है। आर्थिक मामलों के तमाम जानकार एवं बड़े संस्थान भारत की तेजी से बढती अर्थव्यवस्था को एक महान उपलब्धि के रूप में स्वीकार भी रहे हैं। इनके द्वारा राजग सरकार की तमाम योजनाओं की प्रशंसा भी की गयी है। ऐसा बिलकुल नहीं है कि यह सब संयोग वश हुआ है बल्कि इसके पीछे सरकार द्वारा की गयी अथक मेहनत एवं इसकी लोक हित को समर्पित योजनाएं हैं। भारत के अर्थतंत्र में बेहतरी की दिशा में अनेक पहल सरकार द्वारा की गयी है। संप्रग सरकार के समय से चलते आ रहे भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार घोटालों से मुक्त व्यवस्था, विवेकपूर्ण नीति प्रबंधन, एवं पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। भारत में निवेश को बढाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी ने कारोबार में सुगमता की दृष्टि से तमाम प्रयास किए जिनका लाभ देश को मिल रहा है। इसके तहत मेक इन इण्डिया, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना के उद्देश्यों को पूरा करने में भी मदद मिल रही है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी सरकार की दृष्टि एवं उनके प्रयासों की सराहना करता है जिसकी बदौलत देश जीएसटी के माध्यम से "एक राष्ट्र एक कर" के पथ पर आगे बढ़ा है। ऐसी आशा एवं विश्वास है कि संसद के दोनों सदनों से पारित जीएसटी कर सुधार के क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्ण परिवर्तन को अमल में लाने की दिशा में एक कारगर पहल साबित होगी। सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग को सरकार द्वारा संवैधानिक दर्जा दिए जाने के निर्णय की राजग सराहना करता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं सरकार द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर अधिक से अधिक सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास के लिए सहकारी संघवाद को सशक्त करने और वित्तीय संसाधनों के आवंटन में राज्यों की भागीदारी बढाने की दिशा में ठोस काम किए गए हैं। इसके माध्यम से एक ऐसी प्रणाली विकसित करने में सफलता मिली है जिसके तहत राज्य और केंद्र के नेतृत्व साथ मिलकर भारत के हर नागरिक के सशक्तिकरण की दिशा में ठोस प्रयास कर पा रहे हैं। पीछले तीन वर्षों में भारत का हर नागरिक तेजी से हो रहे बदलावों और पारदर्शिता को महसूस किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री एवं उनके नेतृत्व की सरकार बधाई की पात्र है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय एवं प्रगतिशील नेतृत्व में राजग सरकार देश के बहुमुखी प्रगति को समर्पित नीतियों के माध्यम से समावेशी एवं न्यायसंगत विकास को जमीन पर उतारने का काम कर रही है। राजग सरकार ने ऐतिहासिक रूप पारदर्शिता और प्रक्रियागत समस्याओं को कम करने की दिशा में अनेक निर्णय लिए हैं। पिछले तीन वर्षों में सरकार ने देश का विश्वास और संस्थानों के प्रति विश्वसनीयता को मजबूत किया है। सरकार द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की दिशा में मजबूत पहल हुई है। पहली बार इस सरकार ने इस मानसिकता को समाप्त किया है कि एक केंद्रीकृत नीति ही पूरे देश की समस्याओं का समाधान है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने कठोर परिश्रम, अपार निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ देश का नेतृत्व करते हुए मजबूत भारत के निर्माण के पथ पर सतत आगे बढ़ रहे हैं। राजग के सभी घटक और भारत की आम जनता प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गयी इस विकास यात्रा की सहभागी है। राजग यह विश्वास जताता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सामाजिक समानता, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करते हुए समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के प्रति प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार अपनी सफलताओं और चुनौतियों दोनों को एक अवसर के रूप में लेते हुए और बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार अपनी सफलताओं और चुनौतियों दोनों को एक अवसर के रूप में लेते हुए और बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश की जनता से आवाहन करती है कि देश में विकास एवं गरीब कल्याण कार्यक्रमों की निरंतरता हेतु 2019 के चुनावों में भी श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने हेतु संकल्पवान हो।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश की जनता से आवाहन करती है कि देश में विकास एवं गरीब कल्याण कार्यक्रमों की निरंतरता हेतु 2019 के चुनावों में भी श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने हेतु संकल्पवान हो। ■

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1)................................ (2)................................

ईमेल : ....

सदस्यता	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :.................................. दिनांक :............................ बैंक : ....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुबह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

भुवनेश्वर (ओडिशा) में संपन्न भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के निमित्त कार्यक्रमों के चित्र

डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

श्री अमित शाह को प्रतीक–चिह्न भेंटकर स्वागत करते ओडिशा प्रदेश भाजपा नेतागण

भुवनेश्वर में एयरपोर्ट से बैठक स्थल तक मोटरसाइकिल रैली निकालकर श्री अमित शाह का स्वागत करते कार्यकर्तागण

भुवनेश्वर स्थित पार्टी कार्यालय में पं. दीनदयाल उपाध्याय पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन करते श्री अमित शाह एवं वरिष्ठ भाजपा नेतागण

प्रेषण तिथिः (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघरः लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बने कमल संदेश के आजीवन सदस्य

कमल संदेश की कैशलेस सदस्यता लें!

आह्वान

आपको जानकर हर्ष होगा कि 6 दिसम्बर 2016 को पार्टी मुख्यालय में भाजपा 'कमल संदेश' का आजीवन सदस्य बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. **श्री अमित शाह** ने पत्रिका की सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि 'कमल संदेश' भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय पत्रिका है और यह पाक्षिक रूप में हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती है।

हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं 5000/– रुपए का चैक देकर 'कमल संदेश' की आजीवन सदस्यता ली। साथ ही केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर सहित अनेक केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों एवं पार्टी पदाधिकारियों द्वारा आजीवन सदस्यता ग्रहण की गई है।

'कमल संदेश' हिन्दी एवं अंग्रेजी के दोनों अंकों को 5000/– (पांच हजार रुपये) की सदस्यता शुल्क देकर नियमित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब 'कमल संदेश' के लिए कैशलेस भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध है। कृपया 5000/– (पांच हजार) रुपये का योगदान कर आप भी 'कमल संदेश' (हिन्दी+अंग्रेजी) का आजीवन सदस्य बनें।

एक साल (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹350/-	**तीन साल** (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹1000/-
आजीवन (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹3000/-	**आजीवन** (हिन्दी+अंग्रेजी)	—	₹5000/-

'कमल संदेश' के हमारे पाठकों से अनुरोध है कि इसकी सदस्यता लेकर जीवंत वैचारिक आंदोलन के भागीदार बनें।

कैशलेस बना 'कमल संदेश'

सदस्य बनें और बनाएं

☞ **www.kamalsandesh.org, www.bjp.org** पर जाकर कैशलेस भुगतान क्रेडिट/डेबिट/नेटबैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं।

☞ साथ ही दिए बार कोड से मोबाइल द्वारा सीधा भुगतान भी कर सकते हैं।

chillr
ACCEPTED HERE
Scan the QR code to make a payment
Click on SCAN & PAY and enter amount
Add this contact to pay
+91 9911026172

"**कमल संदेश**" के नाम से कृपया चेक/ड्राफ्ट निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैंः
कमल संदेश, पीपी–66, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली– 110003